● वर्ष-3
● अंक-275
रायपुर, गुरुवार
27 जून 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› इंडियन एयरफोर्स में नौकरी का देख ...

पाकिस्तानी डेलिगेशन कश्मीर पहुंचा

धारा 370 हटने के बाद पहली बार 40 अधिकारियों को भेजा

जम्मू। सिंधु जल संधि के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत की ओर देख रहा है। को जिस स्तर पर भारत ने अलग थलग किया है, उसके बादाम पाकिस्तान भारत की तरफ रहम के तौर पर देख रहा है। बीते कई सालों की अकड़ आखिरकार ढीली होती भी दिखाई दे रही है। धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान का कोई अधिकारी भारत नहीं आया है। लेकिन पाकिस्तान ने 5 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में अपने 40 अधिकारियों को भेज दिया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार पाकिस्तान का डेलिगेशन जम्मू कश्मीर पहुंचा। जैसे ही पाकिस्तानी डेलिगेशन भारत पहुंचा उसे होटल में शिफ्ट कर दिया गया और होटल को सुरक्षाबलों ने घेर लिया। आपको शायद पता न हो लेकिन भारत ने चुपचाप ऐसा खेल कर दिया है जिसने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा।

भारत क्यों आया पाकिस्तान का डेलिगेशन

पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत उसकी तरफ आने वाली नदियों का पानी रोक रहा है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत जम्मू कश्मीर में अपने हिस्सों की नदियों पर तो बांध बना ही रहा है। लेकिन उसके हिस्सों की नदियों पर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा है। वैसे पाकिस्तान जो सोच रहा है वह बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान के हिस्से वाले नदियों पर भी अपने प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि 1960 में सिंधु जल संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ था। तीन पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलुज के पानी

पर भारत को पूरा हक दिया गया। जबकि तीन पश्चिमी नदियां जिनमें झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी के बहाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय हुआ था।

ऐसे में भारत ने अपनी रावि नदी पर बांध बनाकर पानी को पाकिस्तान जाने से तो रोक दिया। लेकिन साथ ही चिनाब और झेलम नदी पर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए। आपको बता दे की इंडस वॉटर ट्रीटी के नियमों के अनुसार भारत पाकिस्तान के हिस्से वाले नदियों का पानी इस्तेमाल भी कर सकता है।

डोडा में मुठभेड़, तीन आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर में डोडा जिले के गंदोह इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ के बाद तीन आतंकवादी मारे गए। वहीं, एक की तलाश अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि ये आतंकवादी घाटी में सेना और पुलिस पर हुए हालिया हमलों में शामिल थे। मुठभेड़ स्थल से अमेरिका निर्मित एम4 कार्बाइन सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि पुलिस को आज सुबह तलाशी अभियान शुरू करने पर तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली। पिछले हफ्ते सिलसिलेवार आतंकी हमलों के बाद डोडा और राजौरी, पुंछ इलाकों में आतंकियों के सफाए के लिए ऑपरेशन तेज हो गए हैं। 11 जून को एक सैन्य शिविर पर हमला किया गया था जिसमें पांच सैनिक और एक विशेष पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे।

आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में कांग्रेस को नहीं मिला एसपी-टीएमसी का साथ!

विपक्षी एकता में पहले दिन ही लग गई सेंध

नयी दिल्ली। आपातकाल पर प्रस्ताव पर समर्थन से लेकर स्पीकर के चुनाव में हार तक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 18वीं लोकसभा के तीसरे दिन बुधवार को विपक्षी एकता पर सवाल उठाए। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि विपक्षी एकता एक मिथक है। इंडिया गठबंधन में कई दलों ने आपातकाल पर प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की। स्पीकर के चुनाव के दौरान ध्वनि मत या मत विभाजन की मांग को लेकर भी विपक्ष में एकमत नहीं था। तीसरी बार फेल राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले दिन ही फेल हो गए। स्पीकर का चुनाव हारना एक बड़ी जीत थी। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), समाजवादी पार्टी (एसपी) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) को उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, वाह, जब कांग्रेस ने आपातकाल की निंदा के प्रस्ताव का विरोध किया तो एसपी, डीएमके, टीएमसी सांसद उससे दूर चले गए! वहां इंडिया गठबंधन चल रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा जहां साधारण बहुमत से दूर है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन को एक दशक के बाद विपक्ष के नेता का पद मिला है।

इस बीच, दावा किया जा रहा है कि एसपी और टीएमसी ने आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे कांग्रेस को निराशा हुई और बीजेपी को खुशी हुई। स्पीकर ओम बिरला ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को याद करते हुए कहा कि सदन इसकी कड़ी निंदा करता है। उन्होंने उन लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना की जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, उसके अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी को बरकरार रखा। बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि यह दिन भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, जिसे उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान पर हमला बताया। अध्यक्ष ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को रेखांकित किया, इसके मूल्यों पर प्रकाश डाला जो बहस और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। बिरला की टिप्पणी के दौरान, कांग्रेस सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाकर विरोध जताया और उस पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया।

नीतीश ने क्यों नहीं मांगा बड़ा मंत्रालय-प्रशांत किशोर

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मोदी कैबिनेट में कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मांगने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। किशोर ने कहा कि कुमार ने अपनी पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष को रोकने के लिए एक प्रमुख मंत्रालय की मांग करने का विकल्प चुना। किशोर ने सुझाव दिया कि बिहार के सीएम को डर है कि अगर उन्होंने किसी और को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया, तो इससे उनके नेतृत्व के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए, कुमार ने ऐसे मंत्रालय को प्राथमिकता दी जहां वह विवादों या आंतरिक विरोध का सामना किए बिना काम कर सकें। यह तब आया है जब बिहार में राजनीतिक परिदृश्य उन आरोपों के बाद गर्म हो गया है कि राज्य को प्रधान मंत्री मोदी की सरकार में कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक स्टंट बताकर खारिज कर दिया। यह चर्चा जद (यू) नेता आरसीपी सिंह के खिलाफ आरोपों के मद्देनजर आई है, जिनके पास पहले एक मंत्रालय था और बाद में उन पर अपनी पार्टी के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया था। सिंह अंततः भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें इस्पात मंत्रालय दिया गया। किशोर ने नेताओं को उनके प्रदर्शन और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के आधार पर चुनने के महत्व पर जोर दिया।

ओवैसी को लोकसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग

मथुरा-काशी की लड़ाई लड़ने वाले वकील ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

नई दिल्ली। सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा लोकसभा में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग बढ़ने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू के समक्ष शिकायत दर्ज की है।

वकील हरि शंकर जैन ने कहा कि इससे साबित होता है कि उनका फ़िलिस्तीन से संबंध है और वे फ़िलिस्तीन से प्रभावित और दबाव में हैं...एक नागरिक के तौर पर मुझे इस तरह की चीज़ को ख़त्म करना होगा। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में, हरि शंकर ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने जो नारा लगाया है वह देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है. यह एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के साथ पठित अनुच्छेद 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल ध्यान देने और उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। हरि

शंकर जैन ने बुधवार को बताया, अगर कोई व्यक्ति भारत के बजाय किसी अन्य देश के प्रति समर्पित है, तो उसे किसी भी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हैदराबाद के सांसद ने मंगलवार को उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने के बाद, ओवैसी ने संविधान निर्माता, बीआर अंबेडकर, उनके राज्य तेलंगाना की सराहना करना जारी रखा और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिससे सत्ता पक्ष में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सांसदों की आपत्ति के बाद, औवेसी ने अपने कृत्य का बचाव करते हुए सदन के बाहर मीडिया से कहा कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहने में कुछ भी गलत नहीं है।

ओवैसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित- दक्षिण गोवा के पोंडा तालुका में चल रहे वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के 12वें संस्करण में हैदराबाद के सांसद के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन का आयोजन करने वाली हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा कि राष्ट्र की सेवा करने की शपथ लेते हुए किसी विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा दिखाना न केवल देशद्रोह है, बल्कि राष्ट्रीय अपमान भी है। प्रस्ताव पारित कर मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द 18वीं लोकसभा से अयोग्य घोषित किया जाए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को पांच वर्ष की बकाया सम्मान निधि देने के फैसले के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर गजमाला से सम्मानित किया।

(विस्तृत समाचार पेज 8 पर)

प्रमुख समाचार

सड़कें अच्छी हालत में न हों तो राजमार्ग एजेंसियां टोल न वसूले

नयी दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर सड़कें अच्छी हालत में नहीं हैं तो राजमार्ग का संचालन करने वाली एजेंसियों को उपयोगकर्ताओं से टोल नहीं वसूलना चाहिए। गडकरी उपग्रह-आधारित टोल संग्रह प्रणाली पर आयोजित एक वैश्विक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस प्रणाली को चालू वित्त वर्ष में ही 5,000 किलोमीटर से अधिक लंबे राजमार्गों पर लागू किया जाना है। गडकरी ने कहा, ''अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा नहीं देते हैं, तो आपको टोल नहीं वसूलना चाहिए। हम उपयोगकर्ताओं से शुल्क वसूलने और अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए टोल वसूलने की जल्दबाजी में हैं।'' उन्होंने कहा, ''आपको उसी जगह पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूलना चाहिए, जहां आप सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क मुहैया करा रहे हैं। अगर आप गड्ढों और कीचड़ वाली सड़कों पर भी टोल वसूलते हैं, तो आपकों लोगों की प्रतिक्रिया का भी सामना करना होगा।'' भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मौजूदा फास्टैग व्यवस्था के भीतर ही वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह व्यवस्था लागू करने की योजना बना रहा है।

केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड मिली

नई दिल्ली। केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड मिल गई है। सीबीआई की तरफ से केजरीवाल की पांच दिन की रिमांड विशेष अदालत से मांगी गई थी। तीन दिन की कस्टडी में भेजे जाने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले आज सुबह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में आप नेता को पेश करने वाली जांच एजेंसी ने कहा कि एजेंसी यह कवायद लोकसभा चुनाव से पहले कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जांच एजेंसी ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में आप सुप्रीमो से पूछताछ की और उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया। आम तौर पर रिमांड के बाद जांच एजेंसी के पास जो सबूत होते हैं उसकी तस्दीक आरोपी से की जाती है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों के साथ आमना सामना भी कराया जाता है।

विस में सर्वसम्मति से पास हुआ देश में जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से जल्द ही जाति आधारित जनगणना कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि केंद्र सरकार को इस बार जाति आधारित जनसंख्या जनगणना को शामिल करते हुए 2021 से अतिदेय जनगणना कार्य तुरंत शुरू करना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन मानता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार में समान अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने के लिए जाति आधारित जनसंख्या जनगणना आवश्यक है। भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। यह प्रमुख विपक्षी अन्नाद्रमुक सदस्यों की अनुपस्थिति में हुआ, जिन्हें कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। अध्यक्ष एम अप्पावु ने कहा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से अपनाया गया।

नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता फैलाने केंद्र की बड़ी तैयारी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय अगले सप्ताह से तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 40 लाख जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग कानूनों के बारे में जागरूक हों और इनका सभी पर, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 5.65 लाख से अधिक पुलिस, जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को पिछले साल लागू किए गए नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। 1 जुलाई से लागू होने वाले ये कानून क्रमशः ब्रिटिश-युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। चूंकि नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है, इसलिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं, जिसके तहत अब सभी मामले हर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जाते हैं।

ईवीएम को नुकसान पहुंचाने वाले वाईएसआरसीपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया

नारासाराओपेटा । आंध्र प्रदेश पुलिस ने युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेता पी रामकृष्ण रेड्डी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उच्च न्यायालय ने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के एक पोलिंग एजेंट पर कथित हमले के मामले में रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पोलिंग एजेंट ने ईवीएम तोड़ने को लेकर रेड्डी से सवाल पूछे थे। माचेरला से पूर्व विधायक रामकृष्ण रेड्डी 13 मई को मतदान वाले दिन निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 202 में घुस गए और ईवीएम को फर्श पर पटक दिया। इस दौरान मतदान केंद्र पर विरोधी दलों के नेताओं के साथ उनकी कथित तौर पर कहासुनी भी हुई। जब तेदेपा कार्यकर्ता ने रेड्डी से सवाल किया तो उन्होंने कथित तौर पर कार्यकर्ता को धमकाया और बाद में अपने समर्थकों को विरोधी दल के कार्यकर्ता के खिलाफ भड़काया। रेड्डी के समर्थकों ने डंडों, छड़ों और चाकुओं से एजेंट पर कथित रूप से हमला किया था। ईवीएम तोड़ने की यह घटना निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए वेब कैमरों में कैद हो गई, .

समाज सेवा करते करते राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर ओम बिरला

प्रो. संजय द्विवेदी

ओम बिरला में ऐसा क्या है जो उन्हें लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी पर पहुंचाता है। अपने कोटा शहर में जरूरतमंद लोगों को कपड़े, दवाएं, भोजन पहुंचाते-पहुंचाते बिरला कब राष्ट्रीय राजनीति के सितारे बन गए, यह एक अद्भुत कहानी है। प्रधानमंत्री ने सदन में उनके द्वारा चलाए जा रहे अनेक सामाजिक कार्यों की चर्चा की। उनकी सरलता,सहजता और सदन चलाने की उनकी क्षमताएं प्रमाणित हैं। अब जब वे ध्वनिमत से लोकसभा के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, तब उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। यह भी शुभ रहा कि कांग्रेस ने प्रारंभिक चर्चाओं के बाद भी मत विभाजन की मांग नहीं की और उनका चयन सर्वसम्मत से हुआ। इससे संसद की गरिमा बनी और परंपराओं का पालन हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए आने वाले समय में लोकसभा ज्यादा बेहतर तरीके से अपने कामों को अंजाम दे सकेगी।

श्री बलराम जाखड़ के बाद वे दूसरे ऐसे सांसद हैं, जिन्होंने यह गरिमामय पद दुबारा संभाला है। इस बात को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि नए सांसदों को बिरला से सीखना चाहिए। मोदी ने कहा कि संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। सदन में आचरण और नियमों का पालन जरूरी है। सदन की गरिमा और परंपराओं का पालन अध्यक्ष की बहुत महती जिम्मेदारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बिरला जी का यह कार्यकाल उदाहरण बनेगा। जहां गंभीर बहसें होंगी और शासकीय काम के साथ विमर्शों का नया आकाश खुलेगा।

राजस्थान के कोटा जिले में 23 नवंबर,1962 को जन्में ओम बिरला का समूचा राजनीतिक और सावर्जनिक जीवन सेवा, समर्पण और उससे उपजी सफलताओं से बना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम प्रारंभ कर वे राजस्थान में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने।

इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे 2003, 2008 और 2013 में तीन बार राजस्थान विधानसभा में विधायक निर्वाचित किए गए। 2014 से वे लगातार तीसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं। इस तरह वे एक सफल जनप्रतिनिधि के रूप में कोटा के लोगों का दिल जीतते रहे हैं। 17 वीं लोकसभा में अध्यक्ष चुने जाते ही वे राष्ट्रीय फलक पर छा गए। अपने तमाम फैसलों की तरह उस समय नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाते हुए बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था। किंतु अपनी सौजन्यता, कुशल सदन संचालन और लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव न होने के बाद भी अकेले वरिष्ठ सांसदों के पैनल के आधार उन्होंने सदन चलाया । उनका सहज अंदाज और हल्की मुस्कान,मीठी डांट से सदन को चलाने का तरीका उन्हें इस बार इस पद का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बना चुका था। अब कोटा की स्थानीय राजनीति से राष्ट्रीय फलक पर आए बिरला सदन की उपलब्धि बन चुके हैं।

बिरला राजनीति में आने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े थे। उनके मन में समाजसेवा की भावना इसी संगठन से उपजी और वे विविध प्रकल्पों के माध्यम से इसी काम में रम गए। उन्होंने अपने क्षेत्र में 2012 में परिधान नाम कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके तहत समाज के कमजोर वर्गों को किताबें और कपड़े वितरित किए जाते थे। इसके साथ ही रक्तदान और मुफ्त दवा वितरण के आयोजनों से वे लोगों के दिलों में उतरते चले गए। फिर उन्होंने मुफ्त भोजन कार्यक्रम भी चलाया। उनका संकल्प था उनके लोग भूखे न सोएं। इस तरह वे बहुत संवेदनशील और बड़े दिलवाले सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता की तरह सामने आते हैं। यह उन हाशिए के लोगों की दुआएं ही थीं कि बिरला आज सत्ता राजनीति के शिखर पर हैं। भाजपा को एक दल के रूप में इस बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है और उसकी निर्भरता राजग के सहयोगियों पर बढ़ी है। इसी तरह सदन में प्रतिपक्ष ज्यादा ताकतवर हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी मौजूद होंगे। मोदी की तीसरी सरकार में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलना भी एक बड़ी सूचना है। पिछले दो सदनों में कांग्रेस के इतने सदस्य नहीं थे कि वह नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर सके।

इससे नेता प्रतिपक्ष अब लोकलेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे और सरकारी खर्चों पर टिप्पणी कर सकेंगें। इस बदले हुए परिदृश्य में सदन में प्रतिपक्ष की आवाज भी प्रखर होगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए सत्ता पक्ष पर अंकुश और प्रतिपक्ष को संरक्षण देने की अपील की। उम्मीद की जानी कि ओम बिरला अपने बड़े दिल से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्रदान करेंगें। फिलहाल तो उन्हें शुभकामनाएं ही दी जा सकती हैं।

किडनी पीड़ितों के लिए गरियाबंद में खुला क्रिटिकल केयर सेंटर

यहां अनुसंधान केंद्र भी खुलेगा स्वास्थ्य मंत्री ने दिया आश्वासन

गरियाबंद। जिलेवासियों को स्वास्थ्य मंत्री ने आज बड़ी सौगात दी। सुपेबेड़ा जाने से पहले मंत्री श्यामबिहारी जयसवाल ने गरियाबंद में क्रिटिकल केयर सेंटर का शुभारंभ किया। यहां 24 घंटे नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर तैनात रहेंगे। एंबुलेंस की सुविधा भी मिलेगी। इस मौके पर मंत्री जायसवाल ने कहा, गरियाबंद में भविष्य में अनुसंधान केंद्र भी खोला जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज गरियाबंद जिले के दौरे पर है। सुपेबेड़ा जाकर किडनी पीड़ितों से मिलने से पहले ही मंत्री ने गरियाबंद में सुपेबेड़ा स्पेशल किडनी वार्ड (क्रिटिकल केयर सेंटर) का शुभारंभ किया। इस सेंटर में दो नेफ्रोलॉजिस्ट की ड्यूटी रहेगी। वहीं 5 डॉक्टर भी तैनात रहेंगे। स्पेशल सेंटर के निरीक्षण के बाद मंत्री ने तीन एंबुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर देवभोग के लिए रवाना किया।

मंत्री श्यामबिहारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, गरियाबंद जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए में हमेशा से तत्पर हूं। पहले भी जिले को 5 डॉक्टर दिया था। भविष्य में किडनी रोग के बेहतर उपचार हो सके, इसके लिए जिले में आगामी दिनों में अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने जिला अस्पताल के लिए नवीन भवन की मंजूरी आने वाले बजट में दिलाने की बात कही।

मंत्री जायसवाल को भाजपा नेताओं ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल आज बुधवार को पहली बार एक दिवसीय दौर पर गरियाबंद पहुंचे। इस मौके पर स्थानीय सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मंत्री जायसवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं सुनी और साथ ही निराकरण का आश्वासन भी दिया। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री को जिला मुख्यालय गरियाबंद में रात के समय में भी मेडिकल सुविधा और सोनोग्राफी की व्यवस्था शुरू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

भाजपा युवा मोर्चा के नेता अजय रोहरा ने बताया कि गरियाबंद के जिला अस्पताल में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग रोजाना आते हैं, लेकिन रात के समय वहां चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं। उन्होंने इस समस्या को दर्शाते हुए मंत्री से अपील की है कि इसे तत्काल समाधान किया जाए। इसके साथ ही सोनोग्राफी की सुविधा भी अस्पताल में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने समस्याओं की जानकारी मिलते ही तुरंत जिला स्वास्थ्य अधिकारी से इस मामले पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर जिला महामंत्री अनिल चंद्राकर, सागर मयाणी, वंश सिन्हा, परमेश्वर सेन, प्रतीक सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ में खुले स्कूल, लेकिन जर्जर भवनों में कैसे होगी पढ़ाई

धमतरी। छत्तीसगढ़ में 26 जून से सरकारी स्कूलों में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो गई। लेकिन धमतरी जिले के कई स्कूल नए शिक्षण सत्र के लिए तैयार नहीं दिख रहे। जिले के कई स्कूलों में अभी भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अगर स्कूल बच्चों के बैठने के लिए और पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो सवाल उठता है कि ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी।

मीडिया की टीम ने धमतरी जिला शिक्षा विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। धमतरी जिले के स्कूलों का दौरा करने पर हमारी टीम ने पाया कि अभी भी बड़ी संख्या में स्कूलों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। इस संबंध में धमतरी के जिला शिक्षा अधिकारी से जब सवाल किया गया, तो उन्होंने दावा किया सभी स्कूलों में साफ-सफाई हो चुकी है और जहां नहीं हुई है, वहां स्कूल खुलने से पहले सफाई करा ली जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी टीआर जगदल्ले ने कहा शासन के आदेशानुसार स्कूल 26 से खुल रहे हैं। सभी स्कूलों में तैयारियां पूरी हो गई है। शिक्षकों की कमी नहीं है। जिले में 1490 स्कूल हैं, भवन पर्याप्त मात्रा में है। प्राचार्यों का मीटिंग बुलाई गई थी। साफ सफाई के लिए बोला गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।

मानसून आ चुका है। बारिश भी शुरू हो चुकी है। स्कूलों में अगर बारिश में खिड़की-दरवाजों या छत पानी अंदर टपक रहे हों, तो उन्हें ठीक करने में समय लगेगा। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूलों में झाड़ियां या पेड़ पौधे बड़ी संख्या में उग जाते हैं, उनकी भी सफाई करना जरूरी है। क्योंकि जहरीले जीव-जंतु कभी भी इन जगहों पर डेरा जमा सकते हैं और किसी अनहोनी की वजह बन सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये सभी काम स्कूल खुलने से पहले क्यों नहीं कराए गए हैं। जरूरत यह है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षण को ध्यान में रखते हुए समय रहते सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए।

स्कूल के पहले दिन बच्चों को मिठाई खिलाकर किया गया शाला में स्वागत

महासमुंद। नए शिक्षण सत्र की शुरूआत आज हो गई है। बच्चों को स्कूलों में तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। जहां बच्चे उत्साह के साथ शाला में प्रवेश किए। वहीं एक बार फिर स्कूल का वातावरण बच्चों के किलकारियों से चहक उठा। जिले के सभी ब्लॉक में शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया। शाला प्रबंधन समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में स्कूलों का शाला प्रवेशोत्सव की तिथि का निर्धारण किया गया है। आज महासमुंद के नयापारा स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय में विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा के मुख्य आतिथ्य में शाला प्रवेशोत्सव आयोजित किया गया। यहाँ गणवेश, पुस्तक और नव प्रवेशी बच्चों को तिलक, रोली लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्रीमती अनिता जी रावटे, पार्षद श्रीमती मीना वर्मा, श्री रमेश साहू, श्री गोपाल वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री मोहन राव सावंत सहित स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, बच्चे और पालकगण उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने संबोधित करते हुए कहा कि शाला प्रवेशोत्सव से बच्चों के मन में उत्साह का संचार होता है। राज्य सरकार प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तकें और गणवेश उपलब्ध कराती है ताकि स्कूल खुलने के पहले दिन से ही बच्चे अध्ययन में जुट जाए।

रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार एसडीएम का रीडर

भृत्य और सैनिक निलंबित

सरगुजा। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उदयपुर एसडीएम बीआर खांडे, लिपिक धरमपाल, भृत्य अबीर राम और नगर सैनिक कविनाथ को 50 हजार रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही जांच के दौरान एसीबी ने कार्यालय से कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। जिसके मुताबिक, एसडीएम ने प्रार्थी कन्हाई राम और उनके परिवार के सदस्यों से 50 डिसमिल जमीन का पावर ऑफ अटार्नी अपने दो परिचित महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड करा लिया था। इस केस में एसीबी ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई के बाद एसडीएम उदयपुर के लिपिक धरमपाल दास को जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर ने निलंबित किया है। धरमपाल दास सहायक शिक्षक एलबी देवल्लापारा तोलगा में पदस्थ था जबकि एसडीएम ने उसे अटैच कर अपने कार्यालय का रीडर बना रखा था। इसके साथ ही सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा भृत्य अबीर राम को निलंबित किया गया है। अबीर राम भी आकस्मिक स्थापना भृत्य बालक आश्रम देव टिकरा में पदस्थ था, लेकिन उसे भी उदयपुर अटैच कर रखा गया था।

जिला सेनानी ने एसडीएम के गार्ड सैनिक कविनाथ सिंह को निलंबित कर दिया है। कविनाथ सिंह ने रिश्वत की रकम 50 हजार रुपये अपने पास रखी थी। तीनों के निलंबन आदेश मंगलवार को जारी किए गए हैं। वहीं एसीबी द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गए मुख्य आरोपी एसडीएम बीआर खांडे को कलेक्टर ने एसडीएम पद से हटा दिया था और अब उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जानकारी राज्य शासन को भेजी गई है। बड़ी बात यह है कि बीआर खांडे के शासकीय निवास से नगद रकम और जमीनों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

मंगलवार को रिश्वतखोरी के एक और मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने उदयपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ लिपिक नन्हारी राम, सहायक ग्रेड 3 को सस्पेंड कर दिया है। नन्हारी राम ने तहसील कार्यालय में कुमडेवा गांव के एक ग्रामीण से नकल निकालने के नाम पर 200 रुपए रिश्वत मांगी थी। ग्रामीण ने नन्हारी राम को 100 रुपए देना चाहा तो उसने कहा कि दो सौ तो वकील अपने मन से देकर जाते हैं। ग्रामीण द्वारा 200 रुपए देने पर नन्हारी राम ने नकल की प्रतिलिपि दी। शिकायत के बाद कलेक्टर विलास भोस्कर ने नन्हारी राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए सीतापुर तहसील कार्यालय अटैच किया है।

मैं जिंदा हूं, मरा बताकर रोक दी गई है किसान सम्मान निधि

बालोद। बालोद जिला से अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक किसान को मरा बताकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त रोक दी गई है। अब किसान अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर है।

जिले के गुरुर तहसील अंतर्गत ग्राम भोथली निवासी अखिलानंद साहू ने बताया कि कोरोना काल के पूर्व उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक 4 माह में दो-दो हजार की पांच किस्त कुल 10 हजार मिलने के बाद सन् 2021 में कोरोना के बाद से राशि मिलना बंद हो गया।

इस संबंध में जब जानकारी लेने अधिकारियों के पास गया तो बताया गया कि आप योजना के रिकार्ड में मर चुके हो, इसलिए आपकी सम्मान निधि की किश्त रोक दी गई है। इसके बाद से स्वयं के जीवित होने का प्रमाण पत्र लिए आज पर्यंत तक अधिकारियों की चक्कर लगा रहा हूं। कलेक्ट्रेट जनदर्शन पहुंचकर कलेक्टर अपने जीवित होने की प्रमाण देकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त दिलाने की गुहार लगाई।

मामले में अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने कहा शिकायत देखकर मैं भी हैरान हूं। कोई किसी जीवित व्यक्ति को मृत कैसे बता सकता है। इस संबंध में संबंधित एसडीएम कृषि विभाग अधिकारी से प्रतिवेदन लेकर जो भी अधिकारी-कर्मचारी दोषी होगा, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और किसान सम्मान निधि के पात्र होंगे, तो उन्हें राशि दिलाई जाएगी।

कांग्रेस की सोच आज भी इमरजेंसी वाली

साय सरकार ने मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर शुरू की : लखनलाल

कोरबा। पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने साल 1975 के आपातकाल के दौर को याद करते हुए कहा कि 25 जून हमारे देश के इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसियों की सोच आज भी इमरजेंसी वाली ही है। लखनलाल साहू ने यह भी कहा कि कांग्रेसी आज भी देश को तानाशाही सोच से ही चलाना चाहते हैं। आने वाले कल के भविष्य में वे फिर ऐसा न कर सकें, देशवासियों के अधिकारों का दमन और लोकतंत्र को खतरे में न डाल सकें, इसके लिए हम सभी को सहज और सतर्क रहने की जरूरत है।

लखनलाल साहू ने कहा कि उस दौर में भारत के नागरिकों के अधिकारों के हनन का प्रयास हुआ। लाखों मीसा बंदियों को 25 जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक जेल में डाल दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता भी छीन ली गई थी।

लखनलाल साहू ने कहा तब के दौर में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला। उन्होंने न्यायालय में याचिका भी लगाई, जिसमें चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पद और सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल घोषित कर दिया। इस आपातकाल के कारण देश की जनता परेशान हुई।

पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने बताया कि 25 जून 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और दिशा निर्देश में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सभी जिले में मीसा बंदियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। लोगों को जागरूकता और मौलिक अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए प्रयास किए गए। वहीं श्रम, उद्योग और वाणिज्य मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि कोरबा में वर्तमान में एक ही मीसाबंदी रहते हैं। पूर्व ष्टरू डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में मीसाबंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि को विष्णुदेव सरकार में दोबारा शुरू कर दिया गया है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया था। भूपेश सरकार में बंद 5 साल की सम्मान निधि को एकमुश्त मीसाबंदियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एसबीआई बैंक में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी

कोरबा। कोरबा में एसबीआई कर्मी की लापरवाही से भीषण आगजनी हो गई। यहां काम के बाद कर्मी एसी ऑफ करना भूल गए, जिससे बढ़ती गर्मी ने शार्ट सर्किट करा दिया जिससे यहां भीषण आग लग गई। दरअसल, मंगलवार देर रात करीब सवा 12 बजे घंटाघर चौक के पास निहारिका क्षेत्र में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कार्यालय में आग लग गई। आग लगने की जानकारी होते ही यहां आस-पास के लोगों में अपराध अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद तुरंत सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना शुरू किया। आग कैश और जरूरी दस्तावेजों तक पहुंचती उससे पहले ही काबू पा लिया। बैंक के अधिकारी माधवी सिंह ने बताया कि उसे फोन पर घटना की जानकारी मिली, जहां मौके पर पहुंची तो देखा कि ऑफिस में आग लगी हुई है। दमकल वाहन को बुलाया गया, जहां उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया।

बेखौफ बदमाश ने दो लोगों को मारी गोली

दुर्ग। दुर्ग में एक बदमाश ने पुलिस कंट्रोल रूम से महज कुछ ही दूरी पर पिस्टल से दो लोगों को गोली मार दी और फरार हो गया। गोली लगने से दो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज गया, जहां से रायपुर रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला भिलाई नगर थाना के ग्लोब चौक का है, जहां तीन युवक देर रात करीब 2 बजे सरगुजा जिले विश्रामपुर के रहने वाले हैं, जो आपस में गाली-गलौज करते हुए अपने बाइक से जा रहे थे। इसी बीच पीछे से बदमाश अमित जोश अपनी बाइक से उनके पीछे-पीछे पहुंचा। और उनसे झगड़ने लगा। जिसके बाद अमित जोश ने अपने जेब से पिस्टल निकाली और दो लोगों पर फायर कर दिया। दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ अमित जोश की तलाश कर रही है।

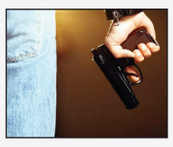

कांग्रेस ने महापौर पद जाने के बाद चुना अपना नेता प्रतिपक्ष

जगदलपुर। जगदलपुर नगर निगम की सत्ता खोने के बाद विपक्ष की भूमिका में आई कांग्रेस ने अपने नेता प्रतिपक्ष का चयन किया है। कांग्रेस नेताओं ने उदय नाथ जेम्स को नेता प्रतिपक्ष चुना है, वहीं राजेश राय को उप नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। दोनों का चुनाव ऑब्जर्वर और भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव एवं कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नरेश ठाकुर की मौजूदगी में हुआ। दरअसल, कांग्रेस की महापौर और अन्य दो पार्षदों के भारतीय जनता पार्टी में जाने की वजह से जगदलपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बन गई थी, जिसके बाद एमआईसी के कांग्रेसी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा के बाद विपक्ष में आई कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष चुनना था, इसके लिए देवेंद्र यादव एवं नरेश ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों ही वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जगदलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष का चयन किया गया।

आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा

उत्तर बस्तर कांकेर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जिले के नरहरपुर में संचालित 100 सीटर्स शासकीय आदिवासी नवीन बालक क्रीड़ा परिसर में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 04 एवं 05 जुलाई को प्रातः 08 बजे से आयोजित किया जाएगा। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि बालक क्रीड़ा परिसर नरहरपुर में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, हैण्डबॉल एवं तीरंदाजी खेल का प्रशिक्षण विधा विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। राज्य के किसी भी विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र जिनकी आयु 21 दिसम्बर 2024 को 18 वर्ष से कम हो, वे नवीन बालक क्रीड़ा परिसर नरहरपुर में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सहायक आयुक्त ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के 100 छात्रों का चयन 10 बैटरी टेस्ट के मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा। खेल का आयोजन बालक क्रीड़ा परिसर नरहरपुर के खेल मैदान में आयोजित की जाएगी एवं प्रवीणता के आधार पर चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।

शिकायतों के निराकरण हेतु जनसमस्या निवारण शिविर

अम्बिकापुर। शासन के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न तहसीलों एवं विकासखण्डों में सम्मिलित दूरस्थ ग्रामों में ग्रामीण जनता से प्राप्त शिकायतों के निराकरण करने हेतु वर्ष 2024 हेतु जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। विकासखण्ड अम्बिकापुर के ग्राम परसा में 05 जुलाई एवं ग्राम सुखरी में 09 अक्टूबर ल को, विकासखण्ड लखनपुर के ग्राम कुन्नी में 19 जुलाई एवं ग्राम बिनकरा में 25 अक्टूबर को, विकासखण्ड उदयपुर के ग्राम देवटिकरा में 02 अगस्त एवं ग्राम केदमा में 13 नवम्बर को, विकासखण्ड लुण्ड्रा के ग्राम असकला में 23 अगस्त एवं ग्राम छेरमुण्डा में 22 नवम्बर को, विकासखण्ड बतौली के ग्राम पोकसरी में 30 अगस्त एवं ग्राम शिवपुर में 29 नवम्बर को, विकासखण्ड सीतापुर के ग्राम पेटला में 13 सितम्बर एवं ग्राम देवगढ़ में 06 दिसम्बर को, विकासखण्ड मैनपाट के ग्राम नर्मदापुर में 27 सितम्बर एवं ग्राम राजापुर में 20 दिसम्बर को शिविर आयोजित होंगे।

गृहमंत्री का सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने किया स्वागत

प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर सोनी को विजय शर्मा ने दी बधाई

बिलासपुर। मंगलवार को राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा बिलासपुर प्रवास पर थे। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल सोनी ने सदरबाजार में श्री शर्मा का जोरदार स्वागत किया। वहीं श्री शर्मा ने भी छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचन पर कमल सोनी को बधाई दी। उन्होंने कमल सोनी का श्रीफल व साल से सम्मान करते हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की इस मौके पर विधायक सुशांत शुक्ला भी मौजूद थे।

सराफा एसोसिएशन के स्वागत से अभिभूत गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सराफा व्यापारियों ने बिलासपुर के युवा नेतृत्व कमल सोनी को अपना अध्यक्ष चुना है। प्रदेश के सराफा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर नवनियुक्त अध्यक्ष कमल सोनी की ओर से जो भी योग्य मांगे आएंगी उसे हमारी सरकार पूरा करेगी और सराफा व्यापारियों के समस्याओं का समाधान करने एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए जल्द बैठक करेगी। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष कमल सोनी के नेतृत्व में सदर बाजार में प्रदेश शासन के गृहमंत्री विजय शर्मा का आतिशबाजी एवं फूलमाला के साथ स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष ने उन्हें अपने निवास पर आमंत्रित भी किया था। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन , बिलासपुर सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश शासन के गृहमंत्री विजय शर्मा का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया। बिलासपुर प्रवास के दौरान शर्मा छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी के सदर बाजार कार्यालय श्री श्याम बगीची परिसर पहुंचे। यहां पर सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने गाजे बाजे के साथ फूल माला से स्वागत किया। श्री शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सराफा व्यापारी संघ के चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष कमल सोनी के नेतृत्व मे व्यापारियों के हित में वे बेहतर काम करेंगे तथा सराफा व्यापार को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। सदर बाजार श्री श्याम बगीची में कमल सोनी के नेतृत्व में गृह मंत्री का स्वागत किया गया यहां पर श्रीमती सरला सोनी, एवं अनेक महिलाओं ने गृहमंत्री का तिलक लगाकर आरती उतारी । प्रवास के दौरान सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी, बिलासपुर सराफा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष राजेश शाह,,सचिव अजय सराफ , आनंद सोनी, मनीष सोनी ,राजेश सोनी ,प्रकाश सोनी, कैलाश सोनी, सजन सोनी, मोतीलाल सोनी ,जितेंद्र सोनी, सूरज सोनी, मुतंजा वनक,मनीष अग्रवाल, प्रियांश सोनी, जितेंद्र सोनी, नवनात के अलावा काफी संख्या में सराफा व्यापारियों ने गृहमंत्री का स्वागत किया।

श्री रामलला दर्शन योजना: 12 श्रद्धालु अयोध्या धाम रवाना

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा राज्य के राम भक्तों के लिए निःशुल्क अयोध्याधाम में श्रीराम के दर्शन कराने हेतु श्रीरामलला दर्शन योजना की शुरूआत की गई है, जिसके तहत् विशेष ट्रेन के माध्यम से प्रत्येक जिलों से श्रद्धालुओं का चयन कर उन्हें रामलला के दर्शन हेतु ले जाया जा रहा है। इसी तारम्य में आज जिला नारायणपुर के 12 रामभक्तों को कलेक्टर श्री बिपिन मांझी ने सायं 5 बजे हरी झण्डी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। ये श्रद्धालु कार से नारायणपुर से दुर्ग फिर दुर्ग से विशेष ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे। कलेक्टर ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। श्रद्धालुओं ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया और बताया कि इस योजना से हम लोगों का श्रीराम के दर्शन करने का सपना पूरा हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत् श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक श्री रूपसाय सलाम, श्री सुदीप झा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी और जाने वाले श्रद्धालु मौजूद थे।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री साय आज होंगें जनता से रूबरू, प्रत्येक गुरुवार होगा जनदर्शन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जनता से रूबरू होकर 27 जून को आम जनता की समस्या को सुनकर त्वरित निराकरण करेंगें। मुख्यमंत्री आमजनों से प्रत्येक गुरुवार जनदर्शन कार्यक्रम में जनता से मुलाकात करेंगें। यह कार्यक्रम हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय जनता से सीधे संवाद करेंगें और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगें। मुख्यमंत्री श्री साय 27 जून को जनदर्शन से मुलाकात कर उनकी समस्या से अवगत होंगे और नागरिकों की समस्याओं को सुनकर एवं उनके यथासंभव त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। इसके साथ ही जनता के सुझाव, शासकीय योजनाओं की उन तक पहुंच की जानकारी भी इस माध्यम से प्राप्त करेंगे।

प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज रहेंगे अंबिकापुर प्रवास पर

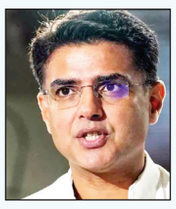

रायपुर। एआईसीसी महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 27 जून गुरूवार को दोपहर 2.25 बजे इंडिगों की नियमित विमान सेवा द्वारा नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे रायपुर एयरपोर्ट से अम्बिकापुर एयरपोर्ट जिला सरगुजा के लिये रवाना होंगे। शाम 4 बजे अम्बिकापुर पहुंचकर श्रीमती इंदिरा सिंह (बेबी राज) को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम 5.20 बजे अम्बिकापुर एयरपोर्ट से रायपुर के लिये रवाना होंगे। रायपुर में रात्रि विश्राम।

आज पुराने दण्ड विधान में बदलाव पर आधारित होगी कार्यशाला

रायपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी ने बुधवार को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, एसएसपी श्री संतोष सिंह के साथ बैठक की। इसमें भारतीय न्याय संहिता-2023 के मूलतत्वों एवं पुराने दण्ड विधान में हुए बदलाव के संबंध में चर्चा हुई। साथ ही इस पर जिला न्यायालय में कार्यशाला का निर्णय लिया गया। यह कार्यशाला 27 जून को शाम 5 बजे जिला न्यायालय परिसर के सभागार में होगा। इसमें न्यायिक, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी अधिवक्तागण और प्रॉसिक्यूटर सहित विधि विशेषज्ञ शामिल होंगे। पुराने दण्ड विधान में बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा। इसमें समाज के सभी वर्गों को जागरूक किया जा रहा। जिसे उन्हें बदलाव के संबंध में जानकारी हो सके।

मानव दिवस सृजन में प्रदेश में रायपुर जिला ने हासिल किया द्वितीय स्थान

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार का सृजन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में भी कार्य किए जा रहे है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सर्वाधिक मानव दिवस सृजन के मामले में प्रदेश में रायपुर जिले ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। मनरेगा श्रमिकों के जिंदगी में व्यापक बदलाव आ रहा है। रायपुर जिले ने वर्ष 2024-25 में जून माह तक आबंटित लक्ष्य के विरूद्ध 159 प्रतिशत मानव दिवस सृजन किया है। रायपुर जिले ने वर्ष 2024-25 में जून माह तक 19.01 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा था, जिसके विरूद्ध जिले में 30.14 लाख मानव दिवस सृजन कर राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में मनरेगा के कार्यों की सतत मॉनिटरिंग हो रही है। इसी का परिणाम है कि मनरेगा के कार्यों को गति मिल रही है। मनरेगा कार्यस्थलों में सभी आवश्यक सुविधाओं के इंतजाम भी किए जा रहे है। श्रमिकों के लिए मेडिकल किट, पेयजल और गर्मी से बचाव के लिए छाया की व्यवस्था की जा रही है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल माह से 10 जून तक प्रतिदिन औसतन 1 लाख श्रमिक जिले में कार्यरत रहे है।

मुख्यमंत्री ने किया लोकतंत्र सेनानियों का शाल, श्रीफल भेंट कर सम्मान

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बुधवार को लोकतंत्र सम्मान समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का शाल, श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग लोकतंत्र सेनानियों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और उनका कुशल क्षेम पूछा। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को पांच वर्ष की बकाया सम्मान निधि देने के फैसले के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर गजमाला से सम्मानित किया। उक्त कार्यक्रम आपातकाल स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया था।

पूर्व माध्यमिक शाला खोखो पारा में मनाया गया शाला प्रवेशोत्सव

रायपुर। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खो खो पारा के संयुक्त में शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया। इस दौरान बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया व मुंहमीठा करा शाला में प्रवेश दिलाया गया। वार्ड पार्षद जितेंद्र अग्रवाल, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व पालकों की उपस्थिति में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। इस अवसर पर पार्षद अग्रवाल व पालकों ने वृक्षारोपण किया गया। न्योता भोज के रूप में पार्षद द्वारा बच्चों व पालकों को फल वितरण किया।

कांग्रेस ने दिया बलौदाबाजार घटना को अंजाम : अरुण साव

रायपुर। बलौदाबाजार घटना को लेकर पीड़ितों के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बलौदाबाजार घटना को अंजाम देने का काम किया है। घटना में कांग्रेस पार्टी की भूमिका सार्वजनिक हो चुकी है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर कहा कि राहुल गांधी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। सभी को अपने राजनैतिक दल के नेता चुनने का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष बनने पर राहुल गांधी को बधाई। प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका होती है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति इन्होंने की है, मुझे नहीं लगता है कि वो निभा पाएंगे।

प्रदेश में आज मनाए जाने वाले शाला प्रवेशोत्सव को लेकर अरुण साव ने कहा कि सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आज से शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। नये प्रवेशी विद्यार्थियों का विद्यालय में स्वागत है। हमारी सरकार अच्छी और गुणवत्ता पूर्व शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री के साप्ताहिक जनदर्शन को लेकर अरुण साव ने कहा कि जनदर्शन में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनकी बातें सुनी जाती है, समस्याओं का निदान होता है। इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। मंत्रिपरिषद के अयोध्या दर्शन पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत ही शीघ्र तिथियां निर्धारित होंगी। सभी रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे।

आरंग में गौ रक्षकों पर एकपक्षीय कार्यवाई को लेकर बजरंग दल के आज जेल भरो आंदोलन पर अरुण साव ने कहा कि सरकार अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। सभी संगठनों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। क़ानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर सभी अपनी भूमिका बना सकते हैं।

कांग्रेस के बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है बयान पर अरुण साव ने कहा कि सरकार का काम आप सभी के सामने है। ये लोकतंत्र है, किसी संगठन को किसी मुद्दे पर बात रखनी है, तो सरकार उनकी बात सुनेगी, समझेगी और संभव कार्यवाई करेगी।

बलौदाबाजार डीएफओ मयंक अग्रवाल के खिलाफ बड़ा एक्शन

बलौदाबाजार। वनमंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल पर मनमानी करने का आरोप लगा था।जिस पर मुख्य वन संरक्षक ने संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच की।जांच के बाद मुख्य वन संरक्षक ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अपना जांच प्रतिवेदन के साथ डीएफओ मयंक अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।आरोप पत्र में डीएफओ मयंक अग्रवाल को उदंडता, हठधर्मिता, अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने का दोषी पाया गया है।आरोप पत्र में प्रशासनिक मर्यादाओं के उल्लंघन की भी बात लिखी गई है।

आपको बता दें कि बेरोजगार इंजीनियर ऋषभ कुमार सोनी, राहुल कुमार और ग्राम देवरूम निवासी नानकेश्वर पटेल ने बलौदाबाजार डीएफओ मयंक अग्रवाल की शिकायत की थी। शिकायत पर मुख्य वन संरक्षक ने डीएफओ मयंक अग्रवाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा है। जिसमें बिंदुवार जानकारी दी गई है।

आरोप पत्र में बताया गया है कि डीएफओ मयंक अग्रवाल ने कार्यों के गुणवत्ता के नाम पर हो रहे अनुपातिक भुगतान और त्रुटि पूर्ण कार्यों में सुधार नहीं करवाकर आवश्यक पहल नहीं की। वन विभाग में प्रति हस्ताक्षर प्रणाली लागू है जिसमें साप्ताहिक भुगतान के निर्देश दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट मैन्युअल 2020 में प्रकाशित है इसका बलौदा बाजार वनमण्डल के प्रत्येक स्तर पर निर्देशों का पालन नहीं किया गया। मनमाने ढंग से वनरक्षक से वनमण्डल स्तर तक कार्य कराकर देयक लंबित रखा जाता है।

आरोप पत्र में ये भी लिखा है कि शेड्यूल एक के वन्यप्राणी तेन्दुओं के शव निपटान के संबंध में सतत् पत्राचार के बाद भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं भेजी गई। वन्य प्राणी के शव के निपटान के संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश का पालन नहीं किया गया।

आरोप पत्र में लिखा गया है कि डीएफओ ने वरिष्ठ अधिकारियों के जांच को कनिष्ठ वनक्षेत्रपाल से दोबारा करवाया। जिसमें दोषी वनरक्षक ने दोबारा जांच में अभिलेख तैयार किया।जबकि मामले का सह आरोपी जांच का हिस्सा बना। मुखिया के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान किया गया। एक वाहन से काम लिया गया जबकि भुगतान कई वाहनों का किया गया।

छत्तीसगढ़ में वार्ड परिसीमन पर घमासान, कांग्रेस की आपत्ति

■ **भाजपा का सवाल किसे बचाना चाहती है कांग्रेस**

रायपुर। रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड हैं। इन 70 वार्डों में नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जानी है। शासन प्रशासन ने तैयारी कर ली है, लेकिन इसके पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि जब साल 2011 को आधार बनाकर साल 2019 में वार्डों का परिसीमन किया गया था तो अब साल 2024 में इस आधार पर एक बार फिर वार्डों का परिसीमन क्यों किया जा रहा है, जबकि वार्डों का परिसीमन 10 साल बाद होना चाहिए।

महापौर एजाज ढेबर ने आपत्ति दर्ज कराई है। ढेबर का कहना है कि साल 2019 में बताया गया था कि 100 वार्ड बनेंगे। महानगरपालिका निगम बनाया जाएगा। यदि ऐसा होता तो इसका फायदा स्वाभाविक है कि रायपुर को मिलता और केंद्र से फंड आता। निगम क्षेत्र का विकास होता, लेकिन उस दौरान ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर से वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

महापौर एजाज ढेबर ने कहा रायपुर नगर निगम के अंतर्गत लगभग 12 लाख से ज्यादा मतदाताओं की संख्या है। अब लगभग 14000 प्रत्येक वार्ड में मतदाता रहेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन इसका आधार साल 2011 को ही रखा गया है, जो सही नहीं है।

रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का कहना है कि परिसीमन से महापौर को दिक्कत क्यों हो रही है। कुछ वार्ड ऐसे हैं, जहां जनसंख्या अधिक है। कुछ वार्ड में जनसंख्या कम है। जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वह चाहे फिर भाजपा या कांग्रेस के हों, उन्हें काम करने में दिक्कत होती है।

नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा महापौर का परिसीमन का विरोध करना समझ से परे है। यह स्वयं महापौर को संदेह के घेरे में डाल रहा है। आखिर वे परिसीमन से पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या कुछ अनैतिक लोग हैं, जिन्हें वार्डों में नहीं रहना था और वह वार्ड वासी बन गए हैं। कुछ लोगों का नाम डिलीट होना था, वह नहीं हो पाया है।

रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के मुताबिक वार्डों में जनसंख्या अलग अलग है। यह सब समान होना चाहिए, जिससे विकास कार्य समान हो। कोई वार्ड यदि दूरस्थ क्षेत्र में जुड़ जाता है तो वहां विकास कार्य नहीं हो पाता है। यह शासन के विचार करने की बात है। शासन इसके लिए सक्षम है। परिसीमन कर सकते हैं और परिसीमन होना भी चाहिए।

राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा कहते हैं कि पॉलिटिकल और व्यवस्था के तहत परिसीमन से अलग अलग नफा नुकसान हो सकता है। परिसीमन साल 2019 में किया गया था। अब यह 10 साल में होना चाहिए। 2019 में किस आधार पर परिसीमन किए थे, क्योंकि कहीं पापुलेशन 14000 तक थी, कहीं 34000 है। कई वार्ड ऐसे भी हैं, जो लंबी दूरी तक रहते हैं। जो वार्ड बनाये गए हैं, उनमें एकरूपता भी लानी चाहिए। उचित शर्मा ने कहा परिसीमन का पक्षधर हूं, लेकिन जैसा परिसीमन राज्य सरकार चाह रही है, शायद उनका विजन कुछ और हो। शायद यह भी चाहते हैं कि वार्ड की पापुलेशन 14-15 हजार के आसपास हो ताकि सुविधा और व्यवस्था देने में थोड़ी आसानी होगी।

वार्ड परिसीमन की जरुरत क्यों ? उचित शर्मा का यह भी कहना है कि जिस तरह साल 2019 में परिसीमन किया गया है, उसका आधार जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। साल 2024 में उसमें क्या अंतर है? क्या कारण है? परिसीमन की जरुरत क्यों पड़ रही है, उसे भी जनता के सामने रखना चाहिए।

27 प्रतिशत वेतन वृद्धि नहीं मिलने से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमृत राव भोंसले के नेतृत्व एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी व कौशलेश तिवारी के मार्गदर्शन में प्रतिनिधिमंडल ने आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री को एक बार फिर 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि एवं ग्रेड पे सहित 18 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मंत्री श्यामबिहारी ने कहा, एनएचएम वालों को बहुत जल्द 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिलेगी और हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि पहले भी मांगों को लेकर आग्रह किया था पर आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अभी तक 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं हुई है। ज्ञात हो कि जुलाई 2023 में बजट सत्र के दौरान सभी विभाग के संविदा कर्मचारियों को 350 करोड़ रुपए 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि के लिए प्रदान किया गया था, जो आज तक स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों को अप्राप्त है।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया, 27 प्रतिशत वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में आक्रोश है। आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उनका स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात बहुत सकारात्मक रहा है और इसमें एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही करने का भरोसा भी दिया गया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल की दिल्ली में पहली धमक, संसद परिसर में की नारेबाजी

■ **दो दर्जन से अधिक सांसदों ने उनका साथ दिया, कांग्रेस से माफी मांगने को कहा**

रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल चाहे रायपुर में हो या दिल्ली में अपनी पहचान बनाने के लिए मोहताज नहीं,दरअसल उनकी मौजूदगी ही पहचान होती है। लोकसभा में उनका पहला सत्र है और संयोगवश आपातकाल के 49 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा परिसर में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने आपातकाल लगाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सांसदों का नेतृत्व किया और जोरदार नारेबाजी की। लगभग दो दर्जन सांसदों ने उनका साथ दिया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा सांसदों सहित सहयोगी गठबंधन दलों के सांसद भी मौजूद थे। श्री अग्रवाल ने संसद की कार्यवाही खत्म होते ही सभी भाजपा सांसदों को एकत्रित किया तथा गांधी प्रतिमा के समक्ष 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल लगाने के फैसले का विराध किया। उसे देश के लिए काला अध्याय बताया। श्री अग्रवाल ने कांग्रेस से इसके लिए माफी मांगने की मांग की। आपातकाल के लिए माफी मांगो, इमरजेंसी के लिए शर्म करो जैसे नारे गूंजाए।

श्री अग्रवाल ने कहा कि आज से 49 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोपी थी। इस दौरान लोगों से उनके मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे। यह भारतीय लोकतंत्र का वह काला अध्याय है जिसे देश की जनता कभी भुला नहीं सकती है। आज आपातकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस व राहुल गांधी से इंदिरा गांधी के कृत्यों पर माफी मांगने की मांग की।

प्रदेश के स्कूलों में फिर से लौटी रौनक

■ **क्लास रूम में गूंजी बच्चों की आवाज, मनाया गया शाला प्रवेशोत्सव**

रायपुर। 26 जून यानी बुधवार से प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने के बाद बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है। बुधवार को स्कूल का पहला दिन था।लिहाजा स्कूलों में बच्चों की संख्या कम दिखी। आने वाले दिनों में बच्चों की संख्या में इजाफा होगा।आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक बार फिर स्कूल खुले हैं।1 मई से लेकर 17 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश था।18 जून को स्कूल खुलने थे।लेकिन गर्मी और हीटवेव के कारण सरकार ने स्कूल खुलने के समय को 1 हफ्ते बढ़ाया था।

स्कूल खुलने के पहले दिन संख्या में कमी ? स्कूल खुलने के पहले दिन हमने स्कूल के टीचर्स से बात की। उन्होंने बताया कि आज स्कूल का पहला दिन है और बच्चों में भी स्कूल खुलने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे हंसी-खुशी खेलने कूदने के साथ ही पढ़ाई करने में लग गए हैं।

टीचर शुभ्रता झा ने कहा स्कूल का पहला दिन होने के कारण आज बच्चों की संख्या जरूर कम है। लेकिन 1 जुलाई तक बच्चों की संख्या फिर से बढ़ जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के तमाम स्कूलों में 2 जुलाई को पढ़ई तिहार का आयोजन किया जाएगा। जिसकी तैयारी स्कूल के स्टाफ कर रहे हैं।

फिर से स्कूल आकर लग रहा अच्छा ? वहीं स्कूली बच्चों के मुताबिक स्कूल का पहला दिन है। स्कूल आकर उन्हें अच्छा लगा। गर्मी की छुट्टियों में उन्हें घर में बोर लगने लगा था। घर में समय व्यतीत नहीं हो रहा था। स्कूल में आने के बाद पढ़ाई लिखाई खेलकूद और अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अच्छा महसूस हो रहा है। आगे भी स्कूल पहुंचकर अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे और खेलकूद में भी हिस्सा लेंगे।

आपको बता दें कि 25 जून तक स्कूल बंद होने के बाद 26 जून से फिर से स्कूल खुले हैं। स्कूल खुलने के बाद सभी सरकारी स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया।जिसमें बच्चों के स्वागत के साथ उन्हें कॉपी और किताबें भी बांटी गई।

पहुंचविहीन क्षेत्रों में सभी आवश्यक सामग्रियों का भंडारण कराएं : श्रीमती शर्मा

■ **वर्षा काल में नदियों के जल स्तर पर सतत् निगरानी रखें**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन पर छत्तीसगढ़ में बाढ़ नैसर्गिक विपत्तियों से निपटने हेतु गठित उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में बरसात के मौसम में राज्य के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ आने पर उससे निपटने की तैयारियों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बाढ़ के दौरान राहत शिविरों की व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं तैयारियों के संबंध विस्तृत चर्चा हुई।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती शर्मा ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में जर्जर भवनों की निगरानी लगातार की जाए। इन भवनों में निवासरत लोगों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से बसाए जाने की भी व्यवस्था की जाए। ऐसे जिले जहां बड़ी नदियां बहती है वहां पर जल स्तर पर बराबर नजर रखी जाए। जल स्तर के खतरे के निशान पर पहुंचने की संभावना होने पर इसकी पूर्व सूचना राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष तथा निचले जिलों को लगातार देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी तरह से बड़े जलाशयों पर कंट्रोल रूम स्थापित कर जल स्तर की जानकारी समय-समय पर शासन को उपलब्ध करायी जाए। बांधों का जल स्तर बढ़ने पर जल निकासी हेतु निचले जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों को 12 घण्टे पूर्व सूचना दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं प्रदेश में कमजोर हो चुके पुल-पुलियों एवं ईमारतों की पहचान कर मरम्मत कर ली जाए। साथ ही बाढ़ के समय दुर्घटना जन्य स्थलों पर सूचना फलक और बेरियर आदि की व्यवस्था करने कहा गया है।

राज्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में इस माह में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। इसलिए सभी जिलों में वर्षा की जानकारी संकलित की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है। इसका दूरभाष क्रमांक 0771-2223471 एवं फैक्स क्रमांक 0771-2223472 है। इसके अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 0771-2221242 दूरभाष पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। जिला स्तर पर भी बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। बैठक में बताया गया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, नमक, केरोसिन, जीवन रक्षक दवाईयां, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा दलों का गठन सहित अन्य जरूरी सामग्री संग्रहित करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए है। बरसात के दिनों में पेयजल स्त्रोतों के आस-पास साफ-सफाई एवं वहां पर ब्लिचिंग पावडर की व्यवस्था करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए गए है। इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्रों की चिन्हांकन कर ली जाए जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इन क्षेत्रों में सतत् निगरानी रखने एवं अवश्यकता पडने पर वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके ठहरने के लिए राहत शिविर आदि की समुचित योजना बनाने के निर्देश दिए गए है। बाढ़ से बचाव संबंधित उपकरणों की मरम्मत करने और जिन जिलों में मोटरबोट उपलब्ध है, उनकी जानकारी शीघ्र ही राहत आपदा नियंत्रण कार्यालय को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में नालियों की साफ-सफाई बरसात के दिनों में निरंतर कराये जाने कहा गया है।

उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, गृह विभाग के सचिव श्री अरूण गौतम, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव श्री चंदन कुमार, विशेष सचिव कृषि श्री सारांश मित्तर और गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण, वित्त विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा, जनसम्पर्क, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगरीय प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, रेल्वे, दूरदर्शन, रेडक्रास सोसायटी, मौसम विज्ञान एवं भारत दूरसंचार निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

नेता विपक्ष का ओहदा तय करेगा राहुल का सियासी भविष्य?

डॉ. रमेश ठाकुर

16वीं और 17वीं लोकसभा में नबंरों के लिहाज से कांग्रेस बीते 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इतना पिछड़ गई थी कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद भी नसीब नहीं हुआ। नेता विपक्ष पद की बात तो दूर, पार्टी का भविष्य और अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया था। कम नंबर संख्या के कारण ही संसद में नेता विपक्ष की सीट भी रिक्त रही। पर, कहते हैं कि सियासत में चमत्कार की संभावनाएं अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती हैं। किसके सितारे बुलंद हो जाए और किसके अचानक बुझ जाएं? इसका दामोदर सब कुछ जनता-जर्नादन के मूड और विचारों पर निर्भर रहता है? बीते 2024 के आम चुनाव में हुआ भी कमोबेश कुछ ऐसा ही? भाजपा 400 पार के नारे के साथ फिर से प्रचंड बहुमत में आने को पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। मौका जरूर दिया, लेकिन आधा-अधूरा? हालांकि, कांग्रेस ने इस बार उम्मीद से कहीं बढ़कर बेहतीन प्रदर्शन कर खुद को लड़ाई में बरकरार रखा। कांग्रेस हो या भाजपा प्रचंड जीत से बौराने की प्रवृति से सभी दलों को तौबा करना होगा। 2024 का जनादेश सभी के लिए सीख जैसा है। कांग्रेस को जनता ने नया जीवनदान दिया है। इसलिए कांग्रेस के सितारे एक बार फिर थोड़े से चमके हैं। पिछली बार मात्र 44 सांसद ही जीतकर संसद पहुंचे थे। पर, ये आंकड़ा इस दफे 99 तक पहुंचा है। तभी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदार हुई है। अच्छे नंबरों से पास होने का ही नतीजा है कि नेता विपक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम पर ताजपोशी होनी विपक्षी धड़े की ओर से मुकर्रर हुई है। पर, जनता का संदेश पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बराबर है? जो जनता के हित में काम करेगा, उसकी जयकार होगी। वरना, घमंड़ चकनाचूर करने में देश के मतदाता जरा भी नहीं हिचकेंगे? 2024 के जनादेश ने देश की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। चाहे प्रधानमंत्री हों या नेता विपक्ष सभी से काम की उम्मीद करती है। नेता भी अब समझ गए हैं कि लच्छेदार बातों और हवा-हवाई दावों से अब काम नहीं चलने वाला? बहरहाल, गठबंधन राजनीति में नेता विपक्ष के पद को पूरे पांच वर्ष तक सुचारू रूप से यथावत रखना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा? पद पर आसीन होने वाले औहदेदार के लिए भी चुनौतियों की भरमार रहेंगी। उन्हें हर घड़ी अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। नेता विपक्ष का पद राहुल गांधी की सियासी समझ की भी कठिन परीक्षा लेगा? क्योंकि सत्तापक्ष और देश की एक बड़ी आबादी अभी तक उन्हें सियासत का 10वीं पास छात्र ही समझती रही है। दरअसल समझने के कई ताजा उदाहण भी सामने मुंह खोले जो खड़े हैं। राहुल गांधी कई बार अपने सियासी प्रयोगों में विगत वर्षों में असफल हुए हैं इसलिए भी लोगों को थोड़ा बहुत संदेह अब भी है? उनके सियासी इतिहास के पन्ने खोले तो सामने एक विफलता भरी तस्वीर उभरती है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी अच्छे से निर्वाह नहीं कर सके, जिसके चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। अमेठी से चुनाव भी हारे और अपनी अगुआई में पार्टी को चुनाव लड़ाकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके। कुल मिलाकर उनके हिस्से में सियासी असफलता की भरमार है। पर, इन गुजरे वर्षों में अच्छी बात ये रही, वह लगातार हारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे, सियासी मैदान में डटे रहे? खुद को साबित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें लोगों का समर्थन हासिल किया। यही कारण है, जनता ने उनपर थोड़ा भरोषा जताया है। खैर, राजनीति में असफलता ज्यादा मायने नहीं रखती, कोई भी हार सकता है। इसलिए ये पुरानी और बेजान बातें ही हैं। सियासत ऐसा अखाड़ा है जहां अच्छे से अच्छा खिलाड़ी चित हुआ है। ताजा उदाहरण मौजूदा लोकसभा चुनाव का परिणाम है जिसमें बड़े से बड़े शूरमा धराशाही हो गए हैं। अपने राजनीतिक कॅरियर में राहुल गांधी पहली मर्तबा कोई संसदीय औहदा संभालने जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा में वह नेता विपक्ष की भूमिका में होंगे, जिसे इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी प्रमुख नेताओं ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

स्पीकर बनते ही बिरला ने पलट दी बाजी

अंकित सिंह

एनडीए उम्मीदवार के ध्वनि मत से चुनाव जीतने के बाद तीन बार के भाजपा सांसद ओम बिरला को बुधवार को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक दुर्लभ सौहार्दपूर्ण क्षण भी देखने को मिला जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिरला को बधाई देने के लिए उनके पास आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ भी मिलाया। जैसे ही सदन ने बिरला के चुनाव पर सराहना की, प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए।

सदन को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि सभी सदस्यों को राष्ट्र के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सदस्यों से सदन में मर्यादा सुनिश्चित करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि संसद (सदन) में विरोध और सड़क पर विरोध के बीच अंतर रहना चाहिए। इसके बाद, उन्होंने सदस्यों से आपातकाल के काले दिनों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दो मिनट के मौन के लिए खड़े होने को कहा। उन्होंने इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया, कांग्रेस को उसके लिए घेरा भी। विपक्ष हक्का-बक्का रह गया। विपक्षी बेंचों ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन स्थगित कर दिया गया।

ओम बिरला ने कहा कि ये सदन 1975 में देश में आपातकाल (इमरजेंसी) लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम, उन सभी लोगों की संकल्पशक्ति की सराहना करते हैं, जिन्होंने इमरजेंसी का पुरजोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में 'लोकतंत्र की जननी' के तौर पर है।

उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद-संवाद का संवर्धन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की गई, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये वो दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया था। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी थीं और न्यायपालिका की स्वायत्तता पर भी अंकुश लगा दिया था। इमरजेंसी का वो समय हमारे देश के इतिहास में एक 'अन्याय काल' था, एक काला कालखंड था।

आपातकाल (इमरजेंसी) लगाने के बाद उस समय की कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए, जिन्होंने हमारे संविधान की भावना को कुचलने का काम किया। क्रूर और निर्दयी मेंटेनेन्स ऑफ इंटरनल सेक्योरिटी एक्ट (मीसा) में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाएं। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसिडिंग्स (प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन) रिपील एक्ट, प्रेस काउंसिल (रिपील) एक्ट और प्रिवेन्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले कालखंड में ही संविधान में 38वां, 39वां, 40वां, 41वां और 42वां संशोधन किया गया।

कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए इन संशोधनों का लक्ष्य था कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाएं, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो और संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सकें। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया गया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड ज्यूडिशियरी की भी बात कही, जो कि उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ऐसी असामाजिक और तानाशाही की भावना से भरी भयंकर कुनीतियां लेकर आई, जिसने गरीबों, दलितों और वंचितों का जीवन तबाह कर दिया।

इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। 1975 से 1977 का वो काला कालखंड अपने आप में एक ऐसा कालखंड है, जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कि कैसे उस समय इन सभी पर हमला किया गया और क्यों इनकी रक्षा आवश्यक है। ऐसे समय में जब हम आपातकाल (इमरजेंसी) के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा, बाबा साहब आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने, इसकी रक्षा करने और इसे संरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

बिरला ने कहा कि हम भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत, देश में कानून का शासन और शक्तियों का विकेंद्रीकरण अक्षुण्ण रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं में भारत के लोगों की आस्था और उनके अभूतपूर्व संघर्ष, जिसके कारण इमरजेंसी का अंत हुआ, और एक बार फिर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, उसकी सराहना करते हैं। 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की क्रूर सच्चाइयों का सामना करते हुए उठा था। 1975 में आज के ही दिन तब की कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट-फैक्टो रेटिफिकेशन किया था, इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मुहर लगाई थी। इसलिए अपनी संसदीय प्रणाली और अनगिनत बलिदानों के बाद मिली इस दूसरी आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए, आज ये प्रस्ताव पास किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि हम ये भी मानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान, गैर-कानूनी गिरफ्तारियों और सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ीं थीं, उनके परिवारवालों को असीमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने ही नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के उस काले कालखंड में, कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश से प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम दो मिनट का मौन रखते हैं।

यह आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ का वर्ष है। सभी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। संविधान के प्रति जागरूकता तभी मजबूत होगी जब युवा पीढ़ी लोकतंत्र के बारे में जानेगी। 50 साल पहले आज ही के दिन 26 जून को कैबिनेट द्वारा आपातकाल का कार्योत्तर अनुसमर्थन किया गया था।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

सुबालोपनिषद् (भाग-20)

गतांक से आगे...

सभी तरह के सत्त्वों (प्राणियों) का हृदय मृत्यु है तथा वह मृत्यु परमादिदेव परमात्मतत्त्व में एक रूप होकर रहता है। इसके बाद न सत् है, न असत् है और न ही सदसत् है। इस तरह यह मोक्ष का उपदेश है, यही वेदों की शिक्षा है, वेदों का अनुशासन है।

पृथ्वी अन्न है, जल अन्न का भक्षण करने वाला है, जल अन्न है तथा ज्योति (तेज या अग्नि) अन्न का भक्षण करने वाली है, ज्योति ही अन्न है, वायु अन्न का भक्षण करने वाली है, वायु ही अन्न है और आकाश अन्न खाने वाला है।

आकाश ही अन्न है तथा इन्द्रियाँ अन्न ग्रहण करने वाली हैं, इन्द्रियाँ ही अन्न हैं, मन अन्न ग्रहण करने वाला है, मन ही अन्न है और बुद्धि अन्न ग्रहण करने वाली है, बुद्धि ही अन्न है तथा प्रकृति अन्न ग्रहण करने वाली है, प्रकृति ही अन्न है और अक्षर अन्न को खाने वाला है, अक्षर ही अन्न है और मृत्यु अन्न को ग्रहण करने वाली है।

यह मृत्यु ही परमदेव परब्रह्म में एक रूप हो जाती है। इसके पश्चात् सत् नहीं है, असत् भी नहीं है, सत-असत् भी नहीं है। यही निर्वाण (मुक्ति) का उपदेश है, यही वेद का अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा है।

इसके पश्चात् रैक्व मुनि ने घोराङ्गिरस से पुनः प्रश्न किया हे भगवन् ! यह विज्ञान स्वरूप आत्मा जब शरीर से बाहर उत्क्रमण करता है, तब वह किसके द्वारा, किस स्थान को जलाता है?

ऐसा सुनकर उन घोराङ्गिरस ने कहा-वह विज्ञानघन आत्मा बाहर उत्क्रमण करता है, तब सबसे पहले प्राण को, क्रमशः अपान को, व्यान को, उदान को, समान को, वैरंभ को, मुख्य को, अन्तर्याम को, प्रभञ्जन को, कुमार को, श्येन को, श्वेत को, कृष्ण को एवं नाग को दग्ध करता है।

क्रमशः ...

बंकिम बाबू ने अपने आलेखों से राष्ट्रीयता का असली अर्थ समझाया

मृत्युंजय दीक्षित

भारत के स्वतंत्रता संग्राम को वंदेमातरम मंत्र ने अद्भुत शक्ति प्रदान की थी। इस मंत्र के प्रणेता थे महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून 1838 का बंगाल प्रांत के परगना जिले में स्थित कंतलपाड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता मिदनापुर के डिप्टी कलेक्टर थे और माता घरेलू साध्वी महिला थीं।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तब बंकिम स्नातक की परीक्षा दे रहे थे। स्नातक होते ही वे कलकत्ता के डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिये गये। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कानून की परीक्षा भी पास की। सामान्य दैनिक जीवन के साथ-साथ बंकिम बाबू का लेखन कार्य भी चल रहा था। उनकी रचनाएं बांग्ला भाषा में लोकप्रिय हो रही थीं। किंतु अपने को प्रतिष्ठित लेखक होने का श्रेय वे माता-पिता के आशीर्वाद को देते थे। बचपन से ही रामायण-महाभारत के संपर्क में रहना तथा नौकरी के दौरान अलग-अलग स्थानों पर नये-नये लोगों से मेलजोल ने भी उनकी लेखन क्षमता में वृद्धि की।

बंकिम चंद्र ने कुल 15 उपन्यास लिखे। इनमें से आनंदमठ, दुर्गेश नंदिनी, कपालकुंडला, मृणालिनी, चंद्रशेखर तथा राजसिंह आज भी लोकप्रिय हैं। आनंदमठ देवी चौधरानी तथा सीताराम पुस्तकों में उस समय की परिस्थिति का चित्रण है। वे बड़े ही सजग लेखक थे। वह समाज की अच्छाइयों तथ बुराइयों का चित्रण बखूबी किया करते थे। जिसका उदाहरण विषवृक्ष, इंदिरा, युगलांगुरीया, राधारानी, रजनी और कृष्णकांत की वसीयत में देखने को मिलता है। इनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास आनंदमठ हैं जिसने थके हुए भारत में नये प्राण फूंक दिये। आनंदमठ देशभक्तों की कहानी है। इस उपन्यास में एक संन्यासी होता है जो देश के लिये अपना सबकुछ दांव पर लगा देता है। उस संन्यासी की पत्नी इतनी बहादुर है कि मर्दाने वेश में घूम-घूमकर दुश्मनों की जानकारी लेती है। सन 1773 में हुए स्वराज आंदोलन की कहानी है आनंदमठ। उस समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। जनता अंग्रेजों से कांप रही थी। चारों ओर अंधकार पूर्ण वातावरण था। वह उपन्यास खंडों में प्रकाशित हुआ था। इसी में वंदेमातरम की रचना हुयी थी। उपन्यासों के अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने कृष्णा चरित्र, धर्मतत्व, देवतत्व की भी रचना की। साथ ही गीता पर विवेचन भी लिखा। कविताएं भी लिखीं। 1872 में बंगदर्शन पत्रिका प्रारम्भ की। बंगदर्शन के पहले अंक में उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी भावना को अपने विचारों को मातृभाषा में व्यक्त नहीं करेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। देश के महान लेखकों में बंकिम चंद्र का नाम पहली श्रेणी में ही रहेगा। उनका अधिकांश लेखन बंगाली में हुआ है किंतु उसमें भारतीय संस्कृति का आधार लिया गया है। अपने लेखन में उन्होंने सामाजिक सुधार भी सुझाये हैं। तत्कालीन समाज अंग्रेज और अंग्रेजियत के प्रति आकर्षित था। वे उन महान लोगों में से थे जिन्होंने भारतीयों में स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। लोग उनके लेखन से राष्ट्रीयता का अर्थ समझ सके।

देश में गठबंधन धर्म की वापसी

मिहिर एस शर्मा

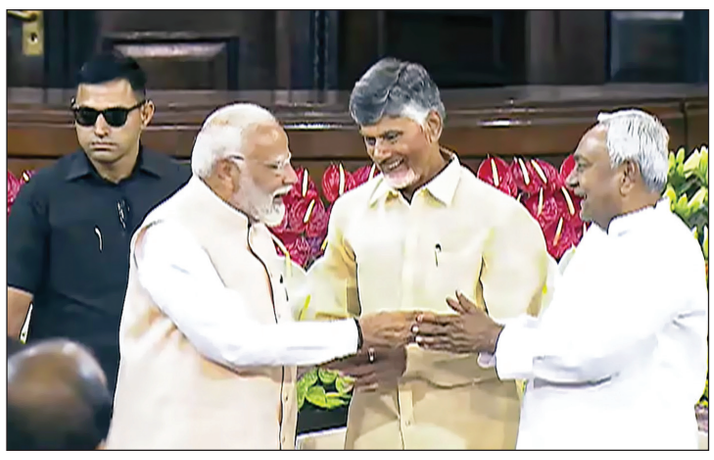

पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसका सबसे बड़ा हासिल यह है कि भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया दोबारा गठबंधन के दौर में वापसी कर चुकी है। अब तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के अहम साझेदार मसलन एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी), नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने मोटे तौर पर कोई खास मांग सामने नहीं रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहम कैबिनेट मंत्रियों को दोबारा उन्हीं पदों पर नियुक्त कर संकेत दिया है कि वह पहले की तरह ही सरकार चलाएंगे। परंतु यह तय नहीं है कि यह दोस्ताना रिश्ता कितने दिन चलेगा? गठबंधन साझेदारों को दिए गए मंत्रालयों पर नजर डालना दिलचस्प हो सकता है। तेदेपा को नागर विमानन मंत्रालय दिया गया है जो पहले भी गठबंधन साझेदारों को दिया जाता रहा है। दिलचस्प है कि रेल मंत्रालय जिसकी अक्सर मांग रहती है वह पुराने अफसरशाह और पिछले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास ही है। साझेदार दलों को दिए गए अन्य मंत्रालय हैं- पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय, इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण, सूक्ष्म और मझोले उपक्रम, कौशल विकास और पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा आदि।

दूसरी ओर इनमें से शायद ही कोई तत्काल नीति निर्माण से जुड़े मंत्रालयों में से कोई पाए। उन मंत्रालयों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के पास ही रहने दिया गया है। इनमें से कुछ ग्रामीण और ग्राम-शहर पर ध्यान देने वाली हैं। उदाहरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण का नाम लिया जा सकता है। अन्य मंत्रालयों का बड़े कारोबारों के साथ करीबी रिश्ता है, मिसाल के तौर पर नागर विमानन और इस्पात। इनमें से कम से कम एक यानी कौशल विकास और उद्यमिता आने वाले समय में नीति निर्माण का एक बड़ा केंद्र होगी। यह मंत्रालय राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया और जाट नेता जयंत चौधरी को दिया गया है। चौधरी की पार्टी के पास महज ढाई साल पहले तक केंद्र या राज्य के स्तर पर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि तक नहीं था। यह एक तरह से धन्यवाद ज्ञापन है क्योंकि वह राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के इलाकों में युवाओं में असंतोष को कम करने की क्षमता रखते हैं। अब उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है।

यह निश्चित नहीं है कि उन्हें यह मंत्रालय अन्य साझेदारों की तुलना में अधिक विश्वसनीय मानकर दिया गया है या फिर कौशल विकास इस सरकार की प्राथमिकता में नीचे है। परंतु यह यह भय तो बना ही रहेगा कि गठबंधन के साझेदार अपनी जमीन बचाते हुए व्यापक सरकारी नीतियों को बाधित भी करेंगे। उदाहरण के लिए वित्त मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय दोनों घरेलू कार्बन कीमतों को लेकर किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। क्या जनता दल सेक्युलर नेता तथा इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी इसमें साथ देंगे? या फिर वह ऐसे किसी भी बदलाव को रोक देंगे जिसके बारे में उनके अफसरशाह उन्हें बताएं कि इससे निजी और सरकारी क्षेत्र की बड़ी इस्पात कंपनियों के मुनाफे और राजस्व में कमी आएगी। कुमारस्वामी पहले ही सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए सरकार द्वारा तय की गई सब्सिडी के आकार पर सवाल उठाकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि गुजरात में सेमीकंडक्टर योजना की बदौलत आने वाले हर रोजगार की लागत करीब 3.2 करोड़ रुपये होगी।

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं में से भी कई अपेक्षित रोजगार नहीं तैयार कर सकीं। इसके बावजूद जैसा कि कुमारस्वामी ने भी बाद में माना योजना का उद्देश्य रोजगार तैयार करना नहीं बल्कि आपूर्ति श्रृंखला के कुछ महत्त्वपूर्ण घटकों का उत्पादन देश में करने की एक महंगी कोशिश है। बहरहाल उनकी आलोचना इस बात का प्रमाण है कि गठबंधन सरकार कैसे काम कर सकती हैं या उन्हें कैसे काम करना चाहिए। हमें यह सुने कितने वर्ष हो चुके जब सरकार के किसी मंत्री ने ठोस वजहों से सरकारी नीतियों की आलोचना की हो? सरकार की पहलों पर खुले में होने वाली और बहसें भी बुरी नहीं होंगी। अगर आप पलटकर 2014 के बारे में सोचें तो इस बात को लेकर संतोष का भाव था कि करीब चौथाई सदी के बाद देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली थी। ऐसा माना जाता था कि गठबंधन धर्म के कारण बहुत सारे सुधारों की राह रुक जाती थी। हर मंत्रालय में गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी और प्रधानमंत्री कार्यालय भी इतना मजबूत नहीं होता था कि चीजों को अंजाम दे सके। निश्चित रूप से इन प्रक्रियाओं में बदलाव आया। प्रधानमंत्री कार्यालय भी मोदी के अधीन अधिक ताकतवर हुआ और मंत्रालयों के सचिव इतने अधिक सशक्त हुए कि वे सत्ता के केंद्र से सीधे बातचीत कर सके।

परंतु वास्तव में विधानों की गुणवत्ता में न तो सुधार हुआ और न ही उनकी गति में तेजी आई। उदाहरण के लिए श्रम कानूनों को नए सिरे से तैयार करने में भी बहुत वक्त लगा लेकिन उनमें बहुत कम बदलाव किए गए। इसके बावजूद चारों नए श्रम कानूनों को अभी भी सही ढंग से पारित और क्रियान्वित होना है। भू अधिग्रहण जैसे विवादास्पद सुधारों के आसानी से पारित होने की उम्मीदें उस समय खत्म हो गईं जब प्रधानमंत्री ने स्वयं विपक्ष के दबाव में उनको वापस ले लिया। इस बीच, प्रस्तावित विधेयकों मसलन नई आपराधिक संहिताओं की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा क्योंकि इन पर सार्वजनिक रूप से, विभागों के बीच और कैबिनेट में भी उनकी उपयोगिता को लेकर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई। ऐसे में दूरदराज की एक संभावना यह है कि गठबंधन का यह नया दौर पिछले एक दशक से ज्यादा नहीं तो भी कम उत्पादक नहीं साबित होगा। राजग में भाजपा के बाद सबसे अधिक सदस्यों वाले साझेदार दल का नाम है नायडू का तेदेपा।

सुधारों और वृद्धि के मामले में उसकी छवि एक अग्रगामी सोच वाले दल की है। जदयू के नीतीश कुमार की छवि सक्षम प्रशासक की है। इन दोनों को विशिष्ट राजकोषीय रियायतें देनी पड़ सकती हैं जिससे राजकोषीय समेकन का काम मुश्किल होगा। परंतु संभव है कि यह प्रगतिशील बदलावों की राह में रोड़ा न बने। यह भी ध्यान देने लायक है कि इस सरकार में भाजपा के आंकड़े लगभग उतने ही हैं जितने कि पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस के थे। 1991 में उसी सरकार ने सुधारों की प्रक्रिया शुरू की थी। पहले की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री के कदमों के लिए असली चुनौती बाहरी नहीं आंतरिक होगी। ये गतिरोध राजनीतिक असर को लेकर उनके आकलन से ही उत्पन्न होते रहे हैं। शायद यह करीबी चुनाव नतीजा यह याद दिलाएगा कि ऐसे राजनीतिक परिणामों का हमेशा कुशलतापूर्वक प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि कुछ जोखिम उठाया जाए और सुधार किए जाएं। गठबंधन उनकी राह नहीं रोकेगा।

आज का इतिहास

1903 19 वर्षीय अमेरिकन आईडा डी अकोस्ता पावर विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी।
1905 रूसी युद्धपोत पोटेमकिन के चालक दल ने अपने दमनकारी अधिकारियों का उत्परिवर्तन शुरू किया।
1914 अमेरिका ने इथोपिया के साथ वाणिज्य संधि पर हस्ताक्षर किये।
1927 जापान के प्रधान मंत्री तनाका गिइची ने चीन के लिए जापान की योजनाओं के बारे में एक सम्मेलन का नेतृत्व किया, जिसमें से तनाका मेमोरियल, इन योजनाओं का विस्तार करने वाला एक रणनीतिक दस्तावेज था (अब माना जाता है कि यह कार्यक्षेत्र है)।
1939 300 से ज्यादा फिल्मों में संगीत देने वाले प्रसिद्ध संगीतकार एवं अभिनेता आर डी बर्मन का जन्म।
1952 ग्वाटेमाला की कांग्रेस ने डिक्री 900 पारित किया, स्थानीय किसानों को 224 एकड़ (0.9 किमी 2) से अधिक आकार की भूमि का पुनर्वितरण किया और देश के भूमि सुधार आंदोलन पर एक बड़ा प्रभाव डाला।
1954 सोवियत संघ का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र ओबिन्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट मास्को के पास ओबनिंस्क में खुलता है। यह दुनिया में पहला ग्रिड-कनेक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन था, यानी पहला परमाणु रिएक्टर जिसने छोटे पैमाने पर व्यावसायिक बिजली का उत्पादन किया। यह भौतिकी और ऊर्जा इंजीनियरिंग संस्थान में स्थित था। संयंत्र को एपीएस -1 ओबनिंस्क (परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1 ओबनिंस्क) के रूप में भी जाना जाता है।
1957 ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ये रिपोर्ट 25 साल के शोध पर आधारित थी।
1967 लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला एटीएम स्थापित किया गया।
1977 फ्रांस ने जिबूती को स्वतंत्रता दी। जिबूती गणराज्य अफ्रीका के हॉर्न में स्थित एक देश है। यह उत्तर में इरिट्रिया, पश्चिम में इथियोपिया और दक्षिण में स्थित है और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से घिरा है। सीमा का शेष भाग पूर्व में लाल सागर और अदन की खाड़ी द्वारा निर्मित है।
1977 अफ़ारों और इस्सास के पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र फ्रांस से स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया और जिबूती बन गया।
1980 इतालवी विमान के तेरीहिंस सागर में दुर्घटनाग्रस्त होने से 81 लोगों की मौत।
1981 कंबोडिया ने अपना संविधान अपनाया।

अलग मोड़ पर दक्षिण की सियासत, केंद्र को सोच-समझकर उठाना होगा कदम

आर. राजगोपालन

दक्षिण भारत की राजनीति एक अलग मोड़ ले रही है। क्या इसके फलस्वरूप मोदी सरकार को दक्षिण में आक्रामक रुख अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा? जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि आंध्र प्रदेश से प्रतिस्पर्धा करते हुए माकपा, द्रमुक और कांग्रेस केरल एवं तमिलनाडु के लिए विशेष वित्तीय दर्जे की मांग कर सकती हैं। चूंकि तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा बन गई है, इसलिए हो सकता है कि उसकी मांग को केंद्र सरकार से समर्थन मिल जाए। इस तरह का विशेष वित्तीय दर्जा उत्तरी राज्य, खासकर बिहार भी मांग रहा है। इसलिए केंद्र सरकार को सोच-समझकर कदम उठाना होगा।

तमिलनाडु में द्रमुक सरकार को फिलहाल सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में कल्लाकुरिची में अवैध जहरीली शराब पीने से 57 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत से लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को इसके लिए कड़ी फटकार लगाई।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी राज्य में शराब त्रासदी की घटना हुई थी, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन राज्य सरकार ने उसे अवैध शराब नहीं, बल्कि मेथनॉल बताया था। इस घटना पर अन्नाद्रमुक और भाजपा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। एमके स्टालिन के नेतृत्व में द्रमुक सरकार के खराब प्रदर्शन के कारण जयललिता की मौत के बाद अन्नाद्रमुक के मरणासन्न अलग-अलग गुटों को जीवनदान मिल रहा है। दक्षिण भारत से 130 सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंचते हैं, उनमें से अधिकांश सांसदों को लगता है कि मोदी सरकार उत्तर भारतीयों के लिए है। इस तरह का नैरेटिव (आख्यान) कई?नेताओं द्वारा प्रभावी ढंग से प्रचारित किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

आग में घी डालने का काम करते हुए तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने जस्टिस चंद्रू की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी गठित की, जिसने राज्य के स्कूलों में दूरगामी सुधारों की सिफारिश की। मोदी के नेतृत्व वाले हिंदुत्व के विकास को रोकने के लिए युवाओं के मन में बदले की भावना के साथ द्रविड़ विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे तमिलनाडु में सामाजिक विभाजन चरम पर है। चंद्रू समिति ने सिफारिश की कि तमिलनाडु सरकार जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए स्कूलों में छात्रों को उनकी जातीय पहचान बताने वाले रंगीन कलाई बैंड या अंगूठी पहनने तथा माथे पर तिलक लगाने से रोके। कमेटी ने स्कूलों के नामों में से जातिसूचक शब्द हटाने की भी सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि माथे से तिलक हटाओ, कुंकुम चंदन नहीं। स्कूली छात्रों को अपने लंबे बालों को गुच्छे की तरह बांधना चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रू की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। हालांकि इस बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि समाज में बदलाव की जरूरत है।

उदाहरण के लिए, स्कूलों के नाम से जाति उपसर्ग जैसे 'कल्लर रिक्लेमेशन' और 'आदि द्रविड़ वेलफेयर' को हटाने और उन्हें सरकारी स्कूल बताने की सिफारिश महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल नाम बदलने से वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। द्रमुक ने 2021 में काफी चुनावी वादा किया था, लेकिन सरकार के स्तर पर उन्हें लागू करने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक एवं तेलंगाना में सरकार है, इसके बावजूद भाजपा ने कांग्रेस को वहां बुरी तरह से पराजित किया। आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी ने 95 प्रतिशत सीटों के साथ विधानसभा में जीत हासिल की। भाजपा वहां तेदेपा और पवन कल्याण की?जनकल्याण सेना के साथ गठबंधन में थी। तमिलनाडु में भाजपा ने अपना वोट शेयर बढ़ाया, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट हासिल करने में विफल रही। जगन रेड्डी का कहना है कि तेदेपा आंध्र प्रदेश में उनके पार्टी कार्यालयों और निजी आवासों को ध्वस्त करके वाईएसआर कांग्रेस से राजनीतिक बदला ले रही है।

जाहिर है, भाजपा को उसकी 'लुक साउथ पॉलिसी' से फायदा मिला है। केरल में पहली बार भाजपा का एक सांसद चुना गया है। लाल दुर्ग में भगवा ने सेंध लगा दी है। संभवत: इसी कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व की हार की समीक्षा करने के लिए केरल के पलक्कड़ में बैठक बुला रहा है। अगर हम विश्लेषण करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह दक्षिण में लोकप्रिय चेहरे हैं। इसी तरह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को भी लोग अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा को चुना। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अल्पसंख्यकों के वर्चस्व वाली आबादी के कारण प्रियंका गांधी वहां आसानी से जीत भी जाएंगी।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने खुलेआम अपने राज्य के लिए अलग झंडा और राष्ट्र गान %जन गण मन% को दरकिनार करके राज्य गान घोषित कर दिया है। दक्षिण में जो कुछ भी हो रहा है, वह गंभीर अध्ययन का विषय है। लेकिन सुधार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऐसे में डर है कि कहीं अलगाववादी मानसिकता सिर न उठा ले। लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान दक्षिण भारतीय नेताओं के भाषणों का विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि अलग दक्षिण आवाज के पीछे कुछ विदेशी शक्तियां हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को इस उभार पर विचार करना चाहिए और इसका गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा राष्ट्र विरोधी ताकतें हावी हो जाएंगी। ऐसी स्थिति राष्ट्रवाद के लिए गंभीर खतरे की चेतावनी है। दक्षिण भारत के छह राज्यों की कहानी से यही सीख मिलती है। अब देखना होगा कि क्या मोदी सरकार इस तरह की मानसिकता को कुचलने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति रखती है!

10 साल बाद लोकसभा को मिला विपक्ष का नेता

नीरज कुमार दुबे

देश को 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता मिल गया है। 2014 और 2019 में चूंकि कोई भी विपक्षी पार्टी लोकसभा चुनावों में इतनी सीटें नहीं जीत सकी थी कि उसे विपक्ष के नेता का पद मिल सके इसलिए यह पद खाली था। पिछली दो लोकसभा में पहले मल्लिकार्जुन खरगे और उनके बाद अधीर रंजन चौधरी एक तरह से विपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इस बार कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाये जाते ही भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। साथ ही, भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश का कितना महत्व है इसे इस बात से समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं और विपक्ष के नेता भी इसी प्रदेश से सांसद चुने गये हैं। देखा जाये तो राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, यदि वह इसे सही से निभा पाये तो यकीनन प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना भी पूरा हो सकता है। राहुल गांधी ने हालिया संपन्न लोकसभा चुनावों में जिन मुद्दों को उठा कर अपनी पार्टी को बड़ी बढ़त दिलाई, यदि वह उन मुद्दों को संसद में भी प्रभावी ढंग से उठा कर देश की जनता की समस्याओं का हल करवा पाये तो वह अपनी उस छवि से बाहर निकल सकते हैं जिसके तहत कहा जाता है कि राहुल गांधी गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं हैं। वैसे विपक्ष का नेता बनते ही जिस तरह राहुल गांधी टी-शर्ट छोड़कर कुर्ते पायजामे में संसद भवन पहुँचे उससे उन्होंने काफी संकेत और संदेश दे दिये हैं। एक दिन पहले हाथ में संविधान की प्रति लेकर लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने वाले राहुल गांधी यदि संसदीय परम्पराओं को आगे बढ़ाते हुए विपक्ष के नेता के रूप में सफल हुए तो भारतीय राजनीति में एक और नया मोड़ देखने को मिल सकता है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि पिछली लोकसभा के दौरान अदालती आदेश के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने पर उनका सरकारी आवास वापस ले लिया गया था लेकिन इस बार वह बतौर विपक्ष के नेता बड़े सरकारी आवास के और कैबिनेट रैंक की सुविधाओं के हकदार होंगे। साथ ही राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कई महत्वपूर्ण चयन समितियों के भी सदस्य हो जाएंगे। यानि अब मोदी से उनका आमना सामना सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि कई समितियों में भी होगा। वैसे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के निर्वाचन के समय राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाकर संकेत दिया है कि वह सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। हम आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2004 में भारतीय राजनीति में कदम रखा और अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ा। यह वही सीट थी जिसका प्रतिनिधित्व उनकी मां सोनिया गांधी (1999-2004) और उनके दिवंगत पिता राजीव गांधी ने 1981-91 के बीच किया था। राहुल गांधी लगभग तीन लाख मतों के भारी अंतर से जीते थे। 2009 में वह फिर जीते लेकिन 2014 में उनकी जीत का अंतर कम हो गया और 2019 में वह स्मृति ईरानी से हार गए थे। राहुल गांधी को 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 16 दिसंबर, 2017 को उन्होंने पार्टी की कमान संभाली।

नागालैंड में पहली बार निकाय चुनावों में महिलाओं को आरक्षण

प्रभाकर मणि तिवारी

पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में बुधवार 26 जून को करीब 20 साल बाद स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि इस चुनाव में पहली बार महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर स्थानीय आदिवासी संगठनों के भारी विरोध और बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा के कारण ही बीस साल से यह चुनाव नहीं कराए जा सके थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्ताक्षर और कड़े रुख की वजह से राज्य सरकार को महिला आरक्षण विधेयक पारित करना पड़ा। यह चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है।

हालांकि, अब भी राज्य के सबसे ताकतवर नागा संगठन ईस्टर्न नागा पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन (ईएनपीओ) ने इस चुनाव के बायकाट की अपील की है। लेकिन अबकी बार इसमें महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ गई है। उसने राज्य के छह पूर्वी जिलों के लोगों से इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेने की अपील की है। यहां इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि हाल के लोकसभा चुनाव में स्थानीय संगठनों की अपील कर छह पूर्वी जिलों में एक भी वोट नहीं पड़े थे। इससे संगठन के असर को समझा जा सकता है।

राज्य के चुनाव आयुक्त टी जे लोंग कुमार बताते हैं- शांतिपूर्ण मतदान की तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। चुनाव की राह में कई कानूनी बाधाएं और चुनौतियां थीं। लेकिन अब उनको दूर कर लिया गया है।

चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस चुनाव में कुल 523 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले कुल 670 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। लेकिन उनमें से 79 ने अपने नाम वापस ले लिए और चार का नामांकन कागजात अधूरे रहने के कारण खारिज हो गया था। मतदान से पहले ही 64 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के सबसे ज्यादा 45 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा भाजपा के सात, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (भाजपा) के पांच, कांग्रेस के तीन, नागा पीपुल्स फ्रंट के दो उम्मीदवारों के अलावा दो निर्दलीय भी शामिल हैं।

राज्य की 39 नगर पालिका और नगर परिषदों की कुल 418 सीटों में से 112 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कोहिमा, दीमापुर और मोकोकचुंग में नगर पालिका परिषद है और बाकी जगह नगर परिषद।

निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। पहली बार यहां किसी चुनाव में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस को सौंपी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक, राज्य के 530 मतदान केंद्रों में से 92 सामान्य, 209 संवेदनशील और बाकी बेहद संवेदनशील हैं।

बीते दो दशकों के दौरान राज्य में इस मुद्दे पर भारी हिंसा होती रही है। वर्ष 2017 में तो इस मुद्दे पर हुई हिंसा में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी और बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ और आगजनी हुई थी। उसके बाद चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। आदिवासी संगठनों के विरोध के कारण तब मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

उस साल राज्य में एक फरवरी को शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदान होना था। इस मौके पर टी आर जेलियांग के नेतृत्व वाली नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) सरकार, जिसमें बीजेपी भी साझीदार थी, ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण पर मुहर लगा दी। लेकिन विभिन्न नागा संगठनों ने बड़े पैमाने पर इसका विरोध शुरू कर दिया।

दूसरी ओर, महिला संगठन नागा मदर्स एसोसिएशन भी अबकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले आरक्षण की मांग पर अड़ा रहा। इसी पर टकराव शुरू हुआ। हालात इतने बेकाबू हो गए कि राज्य में सेना उतारनी पड़ी और हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई। आखिर राज्यपाल ने इन चुनावों को रद्द कर दिया था।

दरअसल, वर्ष 2012 में नागा मदर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में अदालत से शहरी निकायों में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की अपील की थी।

दो साल चली सुनवाई के बाद बीते साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सरकार ने इन चुनावों के लिए मतदान कराने का फैसला किया। उसके बाद महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिल गई।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि नागालैंड पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जहां किसी चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। राज्य में अक्सर राजनीतिक दलों पर महिलाओं की अनदेखी करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब यह चुनाव एक नई मिसाल कायम कर सकता है।

भाजपा नहीं, गठबंधन सरकार के लिए जनादेश

कपिल सिब्बल

लोकसभा चुनाव के 4 जून 2024 के नतीजों ने कुछ दिलचस्प रुझान सामने रखे हैं। हम यह विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि कौन हारा और कौन जीता। सबसे पहले, भाजपा से शुरुआत करते हैं। भाजपा ने इस देश की लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया था और मुख्यधारा का मीडिया मोदी को भारत के लिए सबसे अच्छी चीज के रूप में पेश कर रहा था। इसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के लाभकारी और हानिकारक प्रभाव थे। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस भी कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया या नेतृत्व किया, हर कार्य को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। उनके भाषणों में उनके अपने योगदान की प्रशंसा की गई और विपक्ष, खासकर कांग्रेस की विफलताओं की तीखे शब्दों में निंदा की गई, जिसे सच माना गया।

ऐसा लग रहा था कि मोदी भारत को 21वीं सदी में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं और अपनी पार्टी द्वारा किए गए वादों और दिखाए गए सपनों को पूरा कर सकते हैं। मोदी की मजबूत छवि वाली पार्टी के रूप में भाजपा को एक अभेद्य किला, लगभग अजेय माना जाता था। मोदी ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे उनके रक्षक हैं और आजादी के बाद से कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं। चौबीसों घंटे चलने वाले इस आख्यान का 2019 के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी पर लाभकारी प्रभाव पड़ा। लेकिन 2024 के चुनाव आते-आते यह उबाऊ हो चुका था। मुख्यमंत्रियों सहित केवल विपक्षी नेताओं पर मुकदमा चलाने में जांच एजेंसियों के घोर और अन्यायपूर्ण दुरुपयोग तथा उन्हें चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश ने एक गंभीर चुनावी लड़ाई के दौरान बहुत नकारात्मक संकेत दिया।

आम आदमी, खासकर मध्यम वर्ग को विरोधियों के खिलाफ मुकदमा चलाना और सत्ता प्रतिष्ठान का हिस्सा बनने वाले ऐसे लोगों के प्रति निष्क्रियता बरतना पसंद नहीं आया जिन्हें अत्यधिक भ्रष्ट माना जाता था। वास्तव में, उनमें से कुछ को मुकदमे की धमकी के तहत दलबदल करने और भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। इस तरह की प्रेरित कार्रवाइयों ने दिल्ली और झारखंड सहित कुछ राज्यों में भाजपा को भले ही लाभ पहुंचाया हो, लेकिन मोदी की एकतरफा कार्रवाई प्रतिकूल साबित हुई। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की घोर पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली भी जनता की नाराजगी का एक

कारण थी। चुनाव के बीच में मोदी के दोषपूर्ण बयानों के बावजूद ईसीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया की बदौलत देश के दूरदराज के इलाकों में आम मतदाताओं तक यह बात पहुंची और उन्हें यह पसंद नहीं आया। इसने भी नतीजों को प्रभावित किया।

राज्य विधानमंडलों के कामकाज में राज्यपालों द्वारा हस्तक्षेप, निर्वाचित सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए ऐसी राजनीति में लिप्त होना जो जनता की नजर में भ्रष्ट थी, ने पहले से ही सुलग रहे असंतोष को और बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल द्वारा किए गए युद्धघोष के बावजूद ममता की जीत नहीं रुकी। ममता की लोकप्रियता और चुनावी प्रबंधन ने उनके किले को अभेद्य बना दिया। उन्हें बधाई! मोदी के बारे में बहुत ज्यादा और जमीन पर बहुत कम काम किए जाने की वजह से मोदी एक विवादित व्यक्तित्व बन गए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी कमियां दिखाई गईं और लगभग हर हाथ में मोबाइल फोन होने की वजह से मोदी के प्रति उत्साह धीरे-धीरे खत्म हो गया; मुख्यधारा के टीवी चैनल देखने की तुलना में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना ज्यादा आसान हो गया।

2019 में जिस चीज ने उन्हें फायदा पहुंचाया था, 2024 में उसी ने नुकसान पहुंचाया। यह महसूस करते हुए कि लोकसभा चुनाव के पहले दो चरण बहुत अच्छे नहीं रहे, उन्होंने ऐसे भाषण देने शुरू कर दिए जो उनके पद के अनुरूप नहीं थे। उनका यह कथन कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह अधिक बच्चे पैदा करने वालों को लाभ देगी, सामाजिक विभाजन पैदा करने की कोशिश थी, जिसके बारे में उन्हें लगा कि इससे उन्हें शेष चरणों के चुनाव में मदद मिलेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पार्टी में दिग्गजों और वरिष्ठों को दरकिनार करते हुए उनके द्वारा मुख्यमंत्रियों का चयन किए जाने से असंतोष और बढ़ गया, जो अंतत: मोहन भागवत के बयानों में परिलक्षित हुआ। दूसरे शब्दों में, आरएसएस भी चिंतित था कि मोदी आरएसएस की संस्कृति के साथ असंगत थे, जिसके वे स्वयं प्रचारक हैं। यह मोदी बनाम बाकी था; ऐसा लग रहा था कि भाजपा मोदी के व्यक्तित्व में समा गई थी।

'400 पार' का नारा भी प्रतिकूल साबित हुआ। देश ने बिना किसी संदेह के मोदी को नकार दिया है क्योंकि भारत के लोगों ने भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए वोट नहीं दिया है। यह वोट स्पष्ट रूप से एक वैकल्पिक सरकार के लिए था। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, लोगों की प्रतिक्रिया कुछ हद तक मिली-जुली है। कुछ अपवादों को छोड़कर कांग्रेस को लाभ हुआ। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कांग्रेस को बहुत लाभ हुआ, लेकिन तभी जब उसने संबंधित राज्यों में अन्य प्रमुख दलों के साथ गठबंधन किया। जब बात मध्यप्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों की आई, तो कांग्रेस को नुकसान हुआ। राजस्थान में स्थानीय कारकों जैसे वसुंधरा द्वारा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार न करना, मुख्यमंत्री पद से उन्हें वंचित रखना, और कांग्रेस द्वारा एकजुट प्रयास ने शायद चुनाव परिणामों पर असर डाला।

पंजाब और केरल में लोगों के पास गठबंधन को वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस ने तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन किया, जहां वह पहले से ही सत्ता में थी। सबसे बढ़कर, राहुल की बदौलत 'भारत जोड़ो यात्रा' ने लोगों में जोश भरा। प्रियंका के भाषण केंद्रित और आक्रामक थे, जो मोदी के कांग्रेस विरोधी बयानों का माकूल जवाब थे। इसके अलावा तीन और कारक थे- पहला, महंगाई, जिससे आम लोगों को नुकसान हुआ। दूसरा, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, जहां युवा मोदी से निराश थे। और तीसरा, यह धारणा कि मोदी ने अमीरों के लिए काम किया है-एक ऐसा नैरेटिव, जो सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड के फैसले से भी पुष्ट हुआ। इससे लोगों को लगा कि यह योजना केवल भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए थी। इन्हीं कारणों के चलते मिश्रित परिणाम आए, जिसने कांग्रेस की संख्या को लगभग दोगुना कर दिया, हालांकि लोगों का ध्यान खींचने के लिए यह पर्याप्त नहीं था।

इसलिए, लोगों ने वास्तव में गठबंधन सरकार के लिए वोट दिया, न कि मोदी की एक और जीत के लिए। अब गठबंधन के सहयोगियों को ध्यान रखना होगा कि वे ओडिशा की तरह निगले जाने से बचें। अतीत में अनेक गठबंधन सहयोगियों ने भाजपा छोड़ी है जिनमें अकाली, एआईएडीएमके और बेशक शिवसेना शामिल हैं। मोदी के लिए आने वाला समय उथल-पुथल भरा होगा। अगर कांग्रेस एकजुट हो गई तो 2029 का चुनाव उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा।

अफगानिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा विश्व समुदाय को ठोस कदम उठाने की जरूरत

कुलदीप तलवार

अफगानिस्तान में तालिबान को तीसरा साल हो गया है। 15 अगस्त, 2021 को उन्होंने दूसरी बार सत्ता पर कब्जा किया था। उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं के प्रति उनके रवैये में तब्दीली आएगी। उनको शिक्षा पाने की इजाजत भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत समेत ऐसे बहुत से देश हैं, जो महिलाओं को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान में महिलाओं को कोड़े मारे जाते हैं। हाल ही में तालिबान द्वारा 14 महिलाओं और 60 से ज्यादा लोगों को दंड के तौर पर सार्वजनिक तौर पर कोड़े मारे गए, जिसकी सारी दुनिया में निंदा हो रही है। उल्लेखनीय है कि तालिबान के 1990 के दशक के शासन में भी यही होता था। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएचसीआर ने कहा कि नवंबर, 2022 से अप्रैल, 2023 के बीच अफगानिस्तान में ऐसी शारीरिक सजा के 41 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें 58 महिलाएं और 274 मर्द और बच्चों को अलग-अलग अपराधों के लिए कोड़े मारे गए। नाबालिग और कमसिन बच्चियों को जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। लड़कियों में खुदकुशी करने की प्रवृत्ति काफी बढ़ रही है। तालिबान ने सत्ता संभालते वक्त वादा किया था कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन वे घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकतीं और न ही नौकरी कर सकती हैं। अफगानी महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। तालिबान ने अफगानी महिलाओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए विश्वास दिलाया था, लेकिन वहां हो कुछ और ही रहा है। पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद पर रोक लगा दी है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश ऐसे शासन की मदद नहीं करना चाहते, जिसने लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगा रखी है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वूमेन ने बताया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। उसने वहां महिलाओं का दमन रोकने के लिए वैश्विक कार्रवाई की मांग की है। और कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की हालात में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने आवश्यक हैं। तालिबान ने तीन वर्षों के शासन में सुधार का कोई कदम नहीं उठाया। तालिबान ने सत्ता पर कब्जा करके 70 से ज्यादा ऐसे आधिकारिक फरमान जारी किए हैं। और वे अभी तक कायम हैं, जिसका महिलाओं और लड़कियों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस समय 11 लाख लड़कियां स्कूल नहीं जा रहीं और एक लाख से ज्यादा महिलाएं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। महिलाएं निर्णय लेने का अधिकार हासिल करना चाहती हैं। वे न केवल अपने घरों में, बल्कि सरकार व अन्य स्थानों पर भी अधिकार चाहती हैं, लेकिन उनकी ये मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए उनका दर्जा व परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में 190 देशों का सर्वे किया है। इसमें अफगानिस्तान में महिलाओं को करीब 90 फीसदी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, मुक्ति आंदोलन इत्यादि शामिल हैं। आईएसआईएस सैलानियों पर हमले कर रहा है। इसमें महिलाएं ही ज्यादा प्रभावित होती हैं। चंद दिनों पहले ही आईएसआईएस ने ऐसे हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। अफगानिस्तान में बराबर हजारा बिरादरी शिया नागरिकों पर जुल्म ढा रही है। जब भी शिया बिरादरी के लोग?मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, उनको गोलियों का निशाना बनाया जाता है। पिछले बीस साल में भारत ने अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा विकास कार्य किया है। वह अब भी उसे मानवीय सहायता देने की कोशिश करता रहा है। भारत चाहता है कि अलग-अलग देशों की ओर से दी जा रही मदद का दुरुपयोग न हो और अफगानिस्तान आतंक का अड्डा न बने। इसलिए जरूरी है कि अफगानिस्तान सबसे पहले अपनी जनता का भरोसा जीते। वह जब अपनी आवाम का भरोसा हासिल कर लेगा, तब उसका बदला हुआ रवैया सामने आ सकेगा। फिलहाल कोई भी देश उसे मान्यता नहीं दे रहा है। वहां महिलाओं को जो कोड़ों की सजा दी जा रही है, उसे तुरंत बंद करना होगा और शिक्षा के दरवाजे खोलने होंगे। अफगानिस्तानी महिलाओं के सुरक्षा के लिए विश्व समुदाय को भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

इंडियन एयरफोर्स में नौकरी का देख रहे हैं ख्वाब तो ऐसे करें अप्लाई, यहां देखें हर डिटेल्स

अनन्या मिश्रा

इंडियन एयरफोर्स रक्षा प्रणाली में एक अहम भूमिका निभाती है। इसकी तकनीकी और गैर–तकनीकी शाखाओं जॉब पाने के तमाम अवसर होते हैं। इसमें शामिल होकर आप भी युद्ध, रक्षा और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे तमाम अभियानों का नेतृत्व कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को बचपन से ही ऊंचाईयों से प्यार होता है। ऐसे लोग अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ने की चाहत रखते हैं। अगर आप भी देश की सेवा के साथ आसमान में उड़ने का सपना देखते हैं, तो आप इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कैसे मिलती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस आर्टिकल के जरिए हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स रक्षा प्रणाली में एक अहम भूमिका निभाती है। इसकी तकनीकी और गैर–तकनीकी शाखाओं जॉब पाने के तमाम अवसर होते हैं। इसमें शामिल होकर आप भी युद्ध, रक्षा और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे तमाम अभियानों का नेतृत्व कर सकते हैं। इस दौरान स्ट्रेटेजी बनाने, मैनेज करने और उन्हें लागू करने की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से आप पर होती है।

अग्निवीर वायु

इस योजना के तहत युवा इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं। इन उम्मीदवारों को अग्निवीर वायु कहा जाता है। हालांकि इसकी नियुक्ति सिर्फ 4 साल के लिए होती है। फिर 25 फीसदी अग्निवीरों को नौसेना में परमानेंट नौकरी में शामिल किया जाता है। अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। अग्निवीर बनने के लिए युवाओं के पास 12वीं में सांइस होना जरूरी है। इसके साथ ही मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स में मिलाकर कम से कम 50%अंक होने चाहिए।

NDA

एनडीए के लिए 12वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको UPSC की परीक्षा पास करनी होती है। फिर SSB इंटरव्यू निकालना होता है। एनडीएकी परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। यह परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार की आयु 16.5 से 19.5 साल होनी चाहिए। वहीं उम्मीदवार ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12वीं की परीक्षा पास की हो। 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्र भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है।

CDS

सीडीएस के जरिये युवा भारतीय वायुसेना में परमानेंट कमीशन पा सकते हैं। 20 से 24 वर्ष के युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

लेकिन यह भर्ती सिर्फ अविवाहित पुरुषों के लिए है। CDS में अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। या फिर इंटर में फिजिक्स और गणित के साथ बीई/बीटेक होना चाहिए। लास्ट ईयर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

NCC

NCC के एयर विंग सीनियर डिवीजन के 'C' सर्टिफिकेट के साथ उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में आवेदन कर सकते हैं। इसमें चयनित उम्मीदवारों को परमानेंट और शॉर्ट दोनों कमीशन मिलता है। वहीं महिलाओं को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। इसमें अप्लाई करने के लिए युवाओं की आयु 20–24 साल के बीच होनी चाहिए। सिर्फ अविवाहित महिलाएं और पुरुष NCC स्पेशल एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवार के 12वीं में गणित और फिजिक्स प्रत्येक में न्यूनतम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 60% मार्क्स या समकक्ष के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। या फिर न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष के साथ ओआरबीई/बीटेक किया हो।

AFCAT

फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए उम्मीदवार AFCAT की परीक्षा दे सकते हैं। इसके जरिए आप वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में शामिल होते हैं। बता दें कि शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 साल के लिए होता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 20 से 24 साल होनी चाहिए। सिर्फ अविवाहित महिलाएं और पुरुष इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में उम्मीदवारों के फिजिक्स और गणित दोनों सब्जेक्ट में न्यूनतम 50त्न मार्क्स प्राप्त किए होने चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60त्न मार्क्स के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए।

रूस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए करें अप्लाई, यहां जानिए

अगर आप भी विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखते हैं। रूस की अधिकतर यूनिवर्सिटी सरकारी सहायता प्राप्त स्कॉलरशिप देने के साथ एक समान आवेदन प्रोसेस अपनाती हैं। ऐसे में आप इन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा कर सकते हैं।

कई छात्रों का विदेश में बढ़ने का सपना होता है। लेकिन विदेश में पढ़ाई के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है। ऐसे में अगर आप भी विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखते हैं, तो बता दें कि इसके लिए अब आपको बजट की टेंशन नहीं लेनी होगी। क्योंकि रूस में अधिकतर यूनिवर्सिटी सरकारी सहायता प्राप्त स्कॉलरशिप देने के साथ एक समान आवेदन प्रक्रिया अपनाती हैं। ऐसे में रूस में यूनिफॉर्म स्टेट एग्जामिनेशन या एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद कोई भी विदेशी छात्र स्कॉलरशिप के लिए उसी तरह आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि रूसी छात्र करते हैं।

आपको बता दें कि हर साल रूस सरकार की तरफ से विदेशी छात्रों के लिए राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त सीट्स ऑफर की जाती हैं। साल 2018 में इस तरह की 15 हजार सीट्स दी गई थीं। ऐसे में अगर आप भी विदेश में पढ़ाई के इच्छुक हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको रूस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए उपलब्ध स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

स्कॉलरशिप अमाउंट

रूस सरकार की तरफ से मिलने वाले स्कॉलरशिप में पूरे कोर्स की ट्यूशन फीस, मेंटनेंस अलाउंस और डोरमेटरी अलाउंस आदि शामिल होता है। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप का फायदा लेना चाहते हैं, वह भारत में ऑथराइस्ड व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यूनिर्वसिटी में उपलब्ध स्कॉलरशिप व कोर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए एक बार में 6 विश्वविद्यालय का चुनाव कर सकता है। लेकिन एक फेडरल क्षेत्र में 3 से ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं चुक सकते हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में दो अधिक यूनिवर्सिटी नहीं चुन सकते हैं।

छात्र अपनी पसंद के हिसाब से च्वॉइस भरें और फिर अन्य जरूरी डिटेल्स भरें। इसके बाद अपने सिलेक्शन प्रोसेस में बुलावे का इंतजार करें। वहीं देश के आधार पर ऑपरेटर इंटरव्यू, टेस्ट और परीक्षा का शेड्यूल जारी कर सकते हैं। जिसकी जानकारी छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से मिल सकती है।

यदि आप कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल हैं, तो अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए। छात्रों को एमबीबीएस डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसी कोई बी मेडिकल वजह नहीं है, जिसके कारण छात्र को रूस की यूनिवर्सिटी में न चुना जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एचआईवी टेस्ट भी करवाना होगा।

इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को ऑनलाइन सबमिट करें और हार्ड कॉपी आपरेटर के पास जमा कर दें।

अब विश्वविद्यालय में अपने में अपने कन्फर्मेशन का इंतजार करें।

जर्मनी में इंजीनियरिंग, आईटी और हेल्थकेयर जॉब्स पाने का मौका

'अपॉर्चुनिटी कार्ड' से पा सकते हैं 3 साल का वीसा और नौकरी

जर्मनी की सरकार ने अप्रैल 2024 तक 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों को खाली रहने और वर्ष 2035 तक 70 लाख स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता को देखते हुए Opportunity Card 'अपॉर्चुनिटी कार्ड' लॉन्च किया है। इसे भारतीयों समेत विभिन्न एशियाई देशों के लिए एक बेहतरीन अवसर माना जा रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए 2 वर्ष की अवधि की वोकेशनल ट्रेनिंग या डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए।

जर्मनी में नौकरी की इच्छा रखने वाले इंजीनियरिंग, आइटी और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए काम की खबर। जर्मनी की सरकार ने 'अपॉर्चुनिटी कार्ड' लॉन्च किया है, जो कि यूरोप के बाहर के देशों के नागरिकों को जर्मनी में रहने और एक साल तक जॉब सर्च करने का मौका देता है।

'अपॉर्चुनिटी कार्ड' को भारतीयों समेत विभिन्न एशियाई देशों के लिए एक बेहतरीन अवसर माना जा रहा है क्योंकि भारत से काफी संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जाते हैं। इस मामले में भारत ने 2023 से पहले तक सबसे आगे रहे चीन को पछाड़ दिया है। 'अपॉर्चुनिटी कार्ड' से न सिर्फ जर्मनी में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स बल्कि अन्य भारतीय पेशेवर भी जॉब कर सकते हैं।

इसलिए जर्मनी ने किया लॉन्च?

जर्मनी की सरकार द्वारा 'अपॉर्चुनिटी कार्ड' लॉन्च किए जाने के पीछे मुख्य कारण है स्किल्ड वर्कर्स की कमी। खबरों के मुताबिक, जर्मनी को वर्ष 2035 तक 70 लाख स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता होगी। इंडस्ट्री सेक्टर्स की बात करें तो सबसे अधिक नर्सिंग, फूड एवं बेवरेजेस कंपनियों और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सम्बन्धित स्किल्ड वर्कर्स की जर्मनी में विशेष कमी है। जर्मनी की फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 तक 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां खाली हैं। ऐसे में जर्मन सरकार की 'अपॉर्चुनिटी कार्ड' के माध्यम से स्किल्ड मैनपॉवर की कमी को दूर करने का लक्ष्य है।

'अपॉर्चुनिटी कार्ड' के लिए योग्यता

जर्मनी की सरकार द्वारा दिए जा रहे 'अपॉर्चुनिटी कार्ड' को प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 2 वर्ष की अवधि की वोकेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल डिग्री उत्तीर्ण किया होना चाहिए। साथ ही, जर्मन या अंग्रेजी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। हालांकि, जर्मन भाषा का बेसिक ज्ञान (लेवल ए2) आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जर्मनी में एक साल रहने के लिए 12 हजार यूरो (लगभग 10 लाख) रुपये होने चाहिए।

'अपॉर्चुनिटी कार्ड' के फायदे

जर्मनी सरकार द्वारा दिए जा रहे 'अपॉर्चुनिटी कार्ड' को पाने के बाद प्रोफेशनल्स इसके तहत अब बढ़ाई गई अवधि – 24 माह तक वहां रह सकेंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को 2 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में एक वर्ष जॉब सर्च कर के बाद अधिकतम 3 वर्ष तक रहा जा सकता है।

जर्मनी सरकार ने 'अपॉर्चुनिटी कार्ड' स्कीम के अंतर्गत पार्ट टाइम नौकरी की सीमा को 10 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे कर दिया है। इससे प्रोफेशनल्स को जॉब सर्च करने में आसानी होगी।

'अपॉर्चुनिटी कार्ड' दिए जाने में 40 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

'अपॉर्चुनिटी कार्ड' प्राप्त करने के लिए अप्लीकेशन प्रॉसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी के लिए जर्मन दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट, india.diplo.de पर विजिट कर सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

विपक्ष के के. सुरेश को हराकर बिरला लोकसभा अध्यक्ष बने

नईदिल्ली। भाजपा के ओम बिरला को बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। भाजपा सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने का प्रस्ताव पेश किया। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला 18वीं लोकसभा चुनाव में अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जीत के बाद बधाई दी। भाजपा सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनके साथ कुर्सी पर बैठे। बिरला पिछली लोकसभा में भी अध्यक्ष रह चुके हैं और अगर वे जीतते हैं तो वे 25 साल में दूसरी बार यह पद पाने वाले पहले व्यक्ति होंगे।

मुझे विश्वास है कि लोस अध्यक्ष हमें बोलने की अनुमति देंगे

नईदिल्ली। तीन बार के भाजपा सांसद ओम बिरला मंगलवार को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के सुरेश को एक दुर्लभ मुकाबले में ध्वनि मत से हराया। ओम बिरला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते समय मुस्कुरा रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। उन्होंने ओम बिरला को कुर्सी तक पहुंचाया। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने पर राहुल गांधी ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप हमें बोलने देंगे तीन बार के भाजपा सांसद ओम बिरला मंगलवार को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के सुरेश को एक मुकाबले में ध्वनि मत से हराया। नये अध्यक्ष को उनके आसन तक पहुंचाने से पहले प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने एक दूसरे के साथ संक्षिप्त मित्रता भी साझा की और दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया तथा ओम बिरला का स्वागत किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट में बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत

नईदिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुगर लेवल गिरने के बाद तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें चाय और बिस्किट के लिए कोर्ट रूम से बाहर लाया गया। फिर उन्हें अहलमद के कमरे में ले जाया गया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा एजेंसी को आप सुप्रीमो से अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दिए जाने के बाद बुधवार को सीबीआई ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली। केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। बुधवार को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की हिरासत मांगी।

आतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव

नई दिल्ली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी से मिलने लोकनायक अस्पताल पहुंचे हैं। दिल्ली जल संकट और हरियाणा से पानी की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद 25 जून की देर रात उन्हें यहां लाया गया था। वहीं, पूर्व सांसद और सीपीआई(एम) नेता वृंदा करात भी आतिशी का हाल जानने अस्पताल पहुंचीं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यहां जल मंत्री की स्वास्थ्य की जानकारी लेने आया था। आतिशी बहादुर हैं और लड़ना जानती हैं। वह दिल्ली की जनता के लिए लड़ती रही हैं। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार को अपेक्षित सहायता नहीं दे रही है। उन्होंने केजरीवाल के साथ सबसे अधिक अन्याय किया है। उन्हें फिर से फर्जी मामले में फंसा दिया गया है ताकि वह बाहर ना आ सकें और जनता के बीच ना जा सकें।

जब लोकसभा में अखिलेश की टिप्पणी पर हंस पड़े सांसद

नई दिल्ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा, लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अखिलेश ने कहा, आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बैठे हैं। हमारी अपेक्षा है कि किसी सदस्य की आवाज दबाई न जाए और न ही किसी सदस्य के निष्कासन जैसी कार्रवाई कर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे। अध्यक्ष महोदय आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्यायसंगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं नए सदन में पहली बार आया हूं, जिस सदन से मैं आया हूं, वहां स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची है। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी भी ऊंची होगी...मैं किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप सत्ता पक्ष की तरह ही विपक्ष का भी सम्मान करेंगे। जैसे ही अखिलेश ने स्पीकर की कुर्सी को लेकर बात कही तो सदन के कई सदस्य खिलखिलाकर हंस पड़े।

ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र : प्रधानमंत्री

■ लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर मोदी ने ओम बिरला को दी बधाई

नईदिल्ली। लोकसभा ने बुधवार को ध्वनि मत से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को निचले सदन का अध्यक्ष चुना। बिरला के चुनाव के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि वह अगले पांच वर्षों के लिए अध्यक्ष के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोदी ने संसद के निचले सदन को संबोधित करते हुए बिरला से कहा, आपकी मधुर मुस्कान पूरे सदन को खुश रखती है...पिछली लोकसभा ने आपके नेतृत्व में कई अग्रणी कानून पारित किए।

मोदी ने कहा कि अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में एक बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। हम सबको विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सब का मार्गदर्शन करेंगे और देश की आशाओं-अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ये सदन जो दायित्व निभाएगा, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा में

स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार आपने संभाला है, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनते हुए हम देख रहे हैं। श्रीमान बलराम जाखड़ जी ऐसे पहले अध्यक्ष थे, जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करके, फिर दोबारा स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उनके बाद आप हैं, जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला है।

प्रधान मंत्री ने कहा कि आप जिस प्रकार से एक सांसद के रूप में कार्य करते हैं, वह भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि एक सांसद के रूप में आपकी कार्यशैली हमारे first timer और युवा सांसदों को जरूर प्रेरणा देगी। उन्होंने कहा कि हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति निष्ठा को और अधिक मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी मुझे विश्वास है कि आप तो सफल होने ही वाले हैं। लेकिन आपकी अध्यक्षता में ये 18वीं लोकसभा भी सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनो को पूर्ण करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में, आपकी अध्यक्षता में, संसद ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जब भी 17वीं लोकसभा का जिक्र होगा, आपका नाम सदन की मार्गदर्शक रोशनी के रूप में चमकेगा। विभिन्न विधेयकों के माध्यम से, 17वीं लोकसभा ने विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया, जम्मू और कश्मीर को शेष भारत के साथ एकीकृत किया, नए आपराधिक कानून लाए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की और सामाजिक और राष्ट्रीय कल्याण के लिए कई अन्य मील के पत्थर हासिल किए। इसे आने वाली पीढ़ियाँ आपकी विरासत के रूप में याद रखेंगी।

आपातकाल के खिलाफ संसद के बाहर एनडीए नेताओं का विरोध प्रदर्शन

आपातकाल की 50वीं बरसी पर संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एनडीए नेताओं ने तख्तियां दिखाईं और नारे लगाए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि संविधान के लिए सबसे ज्यादा बोलने वालों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल गांधी का बिना नाम लिए तंज करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने पिता और दादी के नाम पर वोट बटोर रहे हैं, तो क्या वे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेंगे?...उन्हें अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कैसे लोकतंत्र का गला घोंटा गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास में एक काला धब्बा है। पूरे देश को जेलखाने में बदल दिया गया और तानाशाही लागू कर दी गई... वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जानना चाहिए। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि पूरा देश आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है. यह दिन भारत के लोगों के मन में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज से 49 साल पहले इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। करीब डेढ़ लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। भारत के संविधान में 42वां संशोधन लाया गया...संविधान बचाने की बात करने वाले राहुल गांधी को आईना दिखाना जरूरी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 26 जून एक ऐसा दिन है जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया था।

आप को दिल्ली की सत्ता से बाहर करने की प्लानिंग में जुटी कांग्रेस

शुरू कर दी 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी

नईदिल्ली। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मासिक ब्लॉक-स्तरीय बैठकें आयोजित करने, पार्टी के सभी सदस्यों के घरों पर पार्टी के झंडे फहराने और पार्टी में शामिल होने या समर्थन करने के लिए सामाजिक संगठनों, निवासी संघों और गैर सरकारी संगठनों तक पहुंचने का प्रस्ताव पारित किया गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के प्रमुख देवेंद्र यादव ने 2025 में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू करने के लिए पार्टी की बोली के तहत मंगलवार को आदर्श नगर और करावल नगर जिला इकाइयों की कार्यकारी समिति की बैठकों को संबोधित किया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मासिक ब्लॉक-स्तरीय बैठकें आयोजित करने, सभी सदस्यों के घरों पर पार्टी के झंडे फहराने और पार्टी में शामिल होने या समर्थन करने के लिए सामाजिक संगठनों, निवासी संघों और गैर सरकारी संगठनों तक पहुंचने का प्रस्ताव पारित किया गया। यादव ने आदर्श नगर में अपने संबोधन में कहा कि यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि हाल के लोकसभा चुनावों में पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है और लोग एक बार फिर दिल्ली में सुशासन प्रदान करने के लिए पार्टी की ओर देख रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब दिल्ली में अभूतपूर्व विकास हुआ। अब, लोगों को पीने योग्य पानी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है और जलभराव, वायु और जल प्रदूषण के अन्य मुद्दों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस ने दिल्ली में 2024 का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सभी सात सीटों पर जीत हासिल की। आप और कांग्रेस दोनों ने कहा कि उनका गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही सीमित है और इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि दोनों दल विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ेंगे या गठबंधन में।

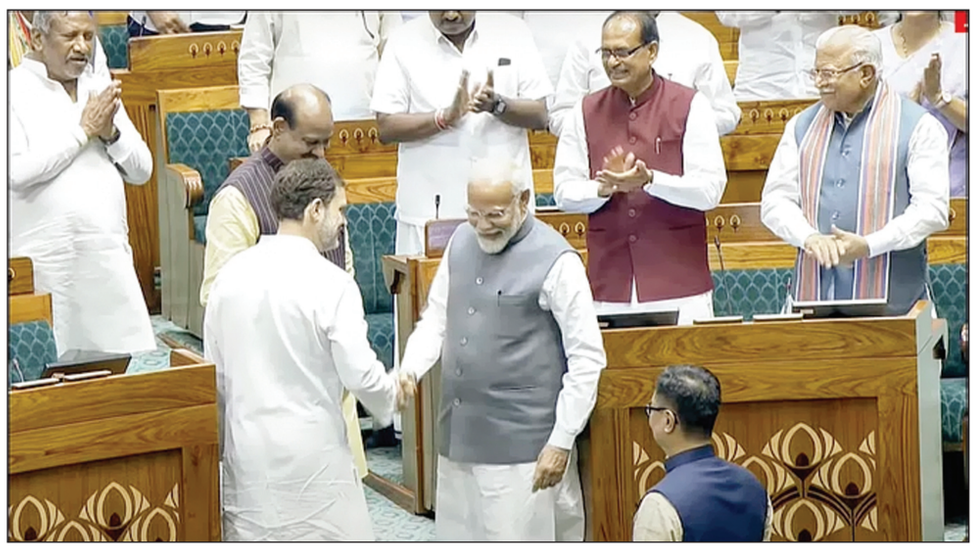

ओम बिरला को आसन तक ले जाते वक्त जब पीएम मोदी की ओर राहुल ने बढ़ाया हाथ

नई दिल्ली। भाजपा सांसद और एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। विपक्ष की ओर से के. सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया।

प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए प्रस्ताव को सभी के सामने रखा और इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। इस दौरान ओम बिरला से हाथ मिलाने के बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी ने एक-दूसरे से भी हाथ मिलाया। जब बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया तो पीएम मोदी, राहुल गांधी और रिजिजू ने उन्हें बधाई और शुभकामना दी। पांचवीं बार ऐसा होगा कि कोई अध्यक्ष एक लोकसभा से अधिक कार्यकाल तक इस पद पर आसीन रहेगा।

खेल
प्रमुख समाचार

सेमीफाइनल में भारतीय टीम की आज इंग्लैंड से होगी भिड़ंत

गयाना। भारतीय टीम का गुरुवार को इंग्लैंड से सामना होगा। सेमीफाइनल का दूसरा मैच गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें टी20 विश्व कप 2024 में पहली बार आमने-सामने होंगी। भारत अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। वहीं, इंग्लैंड को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। हालांकि, जोस बटलर एंड कंपनी ने अमेरिका के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली।

नॉकआउट मैच में भारतीय टीम एक बार फिर रोहित शर्मा की अगुवाई में जोस बटलर की सेना का सामना करती नजर आएगी। टी20 क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच 23 बार भिड़ंत हुई है जिसमें भारत का पलड़ा भारी है। टीम इंडिया को 12 मैचों में जीत मिली है जबकि इंग्लैंड ने 11 मुकाबलों में जीत का स्वाद चखा है। वहीं, टी20 विश्व कप के इतिहास में इंग्लैंड का भारत से चार बार आमना-सामना हुआ है। दोनों ही टीमों ने दो-दो मैच जीते हैं। टी20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराया था। इंग्लैंड ने जोस बटलर और एलेक्स हेल्स की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को करारी शिकस्त दी थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रनों का लक्ष्य तैयार किया था जिसे इंग्लैंड ने 16 ओवर में हासिल कर लिया था। मौजूदा टूर्नामेंट में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

भारत-रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।

इंग्लैंड- फिल सॉल्ट, जोस बटलर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टोन, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, रीस टॉप्ली।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 621 अंक चढ़ा निफ्टी 23,800 के पार

नईदिल्ली। दलाल स्ट्रीट पर बुधवार को लगातार तीसरे दिन तेजी का दौर जारी रहा और बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी नए ऑलटाइम हाई पर पहुंच गए। आज निवेशकों ने भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, आईटीसी और एलएंडटी जैसे दिग्गज शेयरों पर जमकर दांव लगाया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 620.73 अंक यानी 0.80 फीसदी की बढ़त के साथ 78,674.25 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 77,945.94 और 78,759.40 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 147.50 अंक यानी 0.62 फीसदी की बढ़त देखी गई। निफ्टी दिन के अंत में 23,868.80 अंक के नए शिखर पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 23,670.45 और 23,889.90 के रेंज में कारोबार हुआ।

आईसीआईसीआई बैंक के शेयर रिकॉर्ड हाई पर

नईदिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 26 जून को बीएसई पर इंट्राडे ट्रेड के दौरान 1.5 प्रतिशत बढ़ते हुए लगातार तीसरे दिन एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक के शेयरों में पिछले एक साल में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है; जो एक्सिस बैंक के शेयरों से थोड़ा पीछे है। एक्सिस बैंक के शेयर इस अवधि के दौरान 32 प्रतिशत बढ़े हैं। बीएसई सेंसेक्स ने इसी अवधि में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि बीएसई बैंकएक्स 21.3 प्रतिशत बढ़ा है। मंगलवार को, आईसीआईसीआई बैंक मार्केट कैप 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था और यूबीएस के मार्केट कैप को भी पीछे छोड़ दिया था। एनालिस्ट ने बताया कि शेयरों में हालिया तेजी मुख्य रूप से बैंक के वित्तीय परिणामों की वजह से हुई है, जो उनके अनुसार 'सर्वोत्तम' हैं और भविष्य में वृद्धि की संभावना है।

दूसरी तिमाही में 16 फीसदी बढ़ी ऑफिस की मांग

नईदिल्ली। देश में ऑफिस की मांग भी जोर पकड़ रही है। इस साल प्रमुख शहरों में दूसरी तिमाही में ऑफिस की मांग में 16 फीसदी इजाफा हुआ है। इस साल ऑफिस की मांग 5 करोड़ वर्ग फुट के पार जा सकता है। यह तीसरा साल होगा, जब ऑफिस की मांग इस स्तर को पार करेगी। इस साल की दूसरी तिमाही में ऑफिस की नई आपूर्ति में भी इजाफा हुआ है। संपत्ति सलाहकार फर्म कोलियर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस साल दूसरी तिमाही में ऑफिस मार्केट ने अच्छा प्रदर्शन किया और 6 प्रमुख शहरों में 1.58 करोड़ वर्ग फुट ऑफिस की मांग दर्ज की गई। यह पिछली तिमाही यानी इस साल की पहली तिमाही से 16 फीसदी ज्यादा है। इन 6 शहरों में से 4 शहरों में ऑफिस की मांग में 20 फीसदी से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी तिमाही में सबसे अधिक मांग बेंगलूरु में 48 लाख वर्ग फुट दर्ज की गई। इसके बाद 35 लाख वर्ग फुट मांग मुंबई में देखी गई।

स्पेक्ट्रम नीलामी 11,000 करोड़ रु. की बोलियों के साथ समाप्त

नईदिल्ली। मोबाइल रेडियो तरंग सेवाओं के लिए 96,000 करोड़ रुपये मूल्य की स्पेक्ट्रम नीलामी करीब 11,000 करोड़ रुपये की बोलियों के साथ समाप्त हुई। सरकार ने इस नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1,800 मेगाहर्ट्ज, 2,100 मेगाहर्ट्ज, 2,300 मेगाहर्ट्ज, 2,500 मेगाहर्ट्ज, 3,300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की पेशकश की, जिसका आधार मूल्य 96,238 करोड़ रुपये है। सूत्र ने कहा, '' सुबह के सत्र में कोई नई बोली नहीं आई। नीलामी करीब 11,000 करोड़ रुपये की बोलियों के साथ समाप्त हुई है।'' उन्होंने बताया कि भारती एयरटेल नीलामी में सबसे बड़ी बोलीदाता के रूप में उभरी है। पिछली नीलामी 2022 में हुई थी जो सात दिन तक चली थी। उसमें 5जी दूरसंचार स्पेक्ट्रम की रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई थी।

गधों के भरोसे चल रही है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था

योगेंद्र योगी

भारत नित नई टेक्नोलॉजी और अन्वेषण के जरिए अर्थव्यवस्था की तरक्की के परचम विश्व में फहराए हुए है, वहीं दुश्मनी का भाव रखने वाले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गधों के भरोसे टिकी हुई है। भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाली पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और रोजगार गधों के भरोसे चल रही है। गधों की तादाद पाकिस्तान में बढ़ रही है। यह बढ़ती हुई तादाद पाकिस्तान के रोजगार के लिए प्राणवायु बनी हुई है। भारत जहां अपनी अर्थव्यवस्था में लगातार छलांग लगा हुए विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है।

पाकिस्तान आतंकी पालने, गरीबी, कंगाली के लिए विश्व में बदनाम है। गरीबी की हालत यह है कि पाकिस्तान को कर्ज

चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इस हालत में गधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सहारा बने हुए हैं। पाकिस्तान में गधा पालन प्रमुख मवेशी पालन बना हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान में हर साल गधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पाकिस्तान में हाल ही में साल 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। सर्वे में कई आंकड़े सामने आए, लेकिन चुंबक की तरह सबसे ज्यादा ध्यान खींचा गधों की आबादी के आंकड़ों ने। पाकिस्तान में गधों की संख्या लगभग 1 लाख बढ़ी है। कुल गधों की संख्या अब 59 लाख के आस-पास बताई जा रही है।

सर्वे में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में गधों की संख्या में तो इजाफा हुआ है, लेकिन जीडीपीके निर्धारित लक्ष्य पीछे रह गए हैं। दुनिया में गधों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी पाकिस्तान में है, जो इन जानवरों को चीन को निर्यात करके पैसा कमाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने 11 जून को 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान भार ढोने वाले वाले गधों की आबादी देश में लगातार बढ़ी है। साल 2019-2020 में पाकिस्तान में गधों की संख्या 55 लाख के आसपास थी। 2020-21 में ये बढ़कर 56 लाख हो गई। 2021-22 में देश में 57 लाख गधे थे। वहीं 2022-23 में इनकी संख्या 58 लाख थी। पशुपालन पाकिस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। देश में 80 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार पशुधन उत्पादन का काम करते हैं। गधों के आंकड़ों से इतर इकोनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान की जीडीपी के आंकड़े भी बताए गए। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे से पता चला कि पाकिस्तान 2023-24 वित्तीय वर्ष के अपने ग्रोथ रेट के लक्ष्य से पिछड़ गया। देश ने जीडीपी में 2.38 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है, जबकि टारगेट 3.5 प्रतिशत ग्रोथ का था।

रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की खराब प्रदर्शन के कारण हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है जिसने 6.25 प्रतिशत की वृद्धि की है, जबकि लक्ष्य 3.5 प्रतिशत का रखा गया था। औद्योगिक क्षेत्र में ग्रोथ 1.21 प्रतिशत रही जबकि सर्विस सेक्टर ने 1.21 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की। कृषि क्षेत्र में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली, जो कि पिछले 19 सालों में सबसे अधिक है। देश में राजकोषीय घाटा 3.7 प्रतिशत दर्ज किया गया। ये पिछले साल के बराबर रहा। वहीं व्यापार घाटा 4.2 प्रतिशत बना रहा। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पिछले वर्ष के 1 लाख 24 हजार रुपये की तुलना में ये लगभग 10 हजार रुपये बढ़ी है। ये अब 1 लाख 34 हजार रुपये हो गई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार घाटे में चल रहे सरकारी उद्यमों को अपने नियंत्रण से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीईएस में जारी आंकड़ों से पता चलता है कि बोझ ढोने वाले जानवरों में घोड़े और खच्चरों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में कोई खास बदलाव नहीं आया है, तथा यह क्रमशः चार लाख और दो लाख है। गधे कई पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था इन जानवरों के साथ गहरे से जुड़ी हुई है।

लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और तपस्या को कभी भुलाया नहीं जा सकता: साय

आपातकाल स्मृति दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानियों का त्याग-तपस्या और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें सम्मान देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मान निधि देना फिर से शुरू कर दिया गया है और पिछले पांच वर्षों की रोकी गई सम्मान निधि की राशि सेनानियों को एकमुश्त दी जा चुकी है। पिछली सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि को बंद कर दिया था।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज अपने निवास कार्यालय में आपातकाल की 49वीं वर्षगांठ आपातकाल स्मृति दिवस पर आयोजित लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) के सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय बलीराम कश्यप और स्व. नरहरि साय सहित अनेक सेनानियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को शाल, श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर लोकतंत्र सेनानियों ने मुख्यमंत्री श्री साय को चांदी का मुकुट और गजमाला पहनाकर सम्मान निधि पुन: प्रारंभ करने और पिछले पांच वर्षों की राशि देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों को मुख्यमंत्री निवास में सपरिवार आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) ने काफी कष्ट उठाया, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने परिवारों की परवाह न करते हुए जेल गए, जहां उनके साथ बर्बरता की गई, उनके परिवारजनों ने भी काफी कष्ट सहे। कई घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था। जिन परिवारों में कमाने वाले जेल गए ऐसे कई परिवार बरबाद हो गए। देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन सेनानियों ने और उनके परिवारों ने अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था, विपक्षी नेताओं को जेल में बंदकर दिया गया था। मीडिया का अधिकार छीन लिया गया था, लोगों को प्रताड़ित किया गया। इसी की याद में 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने बड़े कष्ट सहे। जो जेल गए उन्होंने जेल में और उनके परिवारों ने जेल के बाहर यातनाएं सही। उनका त्याग बहुत बड़ा है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने घर का अमन-चैन त्यागकर लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी।

बाबू भैया की कलम से ✍

छत्तीसगढ़: बदलाव का दौर और पुराने चेहरों का दर्द

छत्तीसगढ़ में लंबे दौर के बाद राजनीतिक रूप से भारी बदलाव के संकेत बार बार मिल रहे हैं। नेतृत्व की पीढियां जहां बदल रही हैं,वहीं काफी वर्षों से जमे राजनीतिज्ञों की जमीन पोली की जा रही है।सबको अपनी जमीन पर सम्हल कर चलने का संदेश दिया जा रहा है। बदलाव का यह दौर दोनों ही बड़े दलों में चल रहा है। भाजपा ने डॉ. रमनसिंह के नेतृत्व में 15 साल राज चलाने के बाद पांच साल सत्ता से दूर रह कर भाजपा ने शायद कुछ यही सबक लिया है कि किसी एक पर लंबे समय तक राज्य की राजनीति में भरोसा करना हाई कमान की राजनीति के हिसाब से उचित नही होता। जमे जमाए राज नेताओं के थोड़े थोड़े पर कतरते रहने चाहिए ,अन्यथा हाई कमान को कभी कभी राज्य के ये नेता भारी पड़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ हो या मध्यप्रदेश अथवा राजस्थान-हरियाणा-उत्तराखंड-हिमांचल प्रदेश कहीं भी देखिए, हाई कमान ने नए नए विकल्प खड़े करने के बड़े-बड़े प्रयोग किये हैं। भले ही कहीं प्रयोग सफल तो कहीं बुरी तरह असफल रहे हों , लेकिन हाई कमान की यह मंशा तो हर जगह पूरी हुई है कि ,कोई स्थाई छत्रप प्रदेशों में अब दिखना कम हो गया है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर,मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, हमारे छत्तीसगढ़ में डॉ. रमनसिंह के साथ अन्य राज्यों में इस तरह के सफल प्रयोग हो चुके हैं।इसके पीछे हाई कमान की मंशा क्या है ,यह तो पता चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकीन सा है। पर एक बात समझ में जरूर आई है ,कि हाई कमान शायद किसी राज्य में किसी को जम कर रहने नहीं देना चाहता ,ना ही वह किसी को प्रदेशों में स्थाई छत्रप बनने का मौका देना चाहता। अभी हाल एक बडा उदाहरण हमारे प्रदेश में और देखने को मिला। बृजमोहन अग्रवाल जो एक बेहद लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें विधायक बनने टिकट दिया वो जीत भी गए। मंत्री भी बनाया गया। अचानक संसद चुनाव लड़ने का फरमान आ गया। भाजपा हाई कमान के तासीर के अनुसार कहा जा सकता है कि इनकार करना विद्रोह माना जाएगा। बृजमोहन के सामने धर्म संकट की स्थिति ,एक तरफ दिल से चाहने वाली जनता के बीच रहने की तीव्र इच्छा दूसरी तरफ हाई कमान का फरमान। वो जनता जो छात्र जीवन से ही उन्हें सर आंखों पर बैठा रही है। 6 बार विधायक। वो भी एक ही क्षेत्र रायपुर से। दक्षिण सीट का अगाध प्रेम का लम्बा सिलसिला। सामने जो भी प्रतिद्वंदी आया धराशायी हुआ। प्रदेश भर में खासी पहचान। बृजमोहन से मोहनभैया -बिरजू भैया- मोहन बनने तक के सफ़र के सब साथी। बडा ही भावुक समय। अंतत: फैसला हुआ संसद चुनाव लड़ना है। लड़े और आशा के अनुरूप जबरदस्त ऐतिहासिक जीत भी मिली,लोकप्रियता का चरम पैमाना भी दिखाई दिया। प्रदेश से जाने का गम लेकिन भैया केंद्रीय मंत्री बनेंगें की थोड़ी खुशी। सारे सपने धरे रह गए। मंत्री पद उनसे कहीं जूनियर तोखन साहू को मिला। वापस प्रदेश आये तो विधायक का पद छोड़ने का दबाव, विधायकी से इस्तीफा के बाद पहली ही बैठक में मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया। मान-अपमान क्या हुआ समझ में आया नहीं,पर बिदाई के समय निकले आंसू अपनी कहानी खुद ही कह गए ,समझने वालों ने समझ लिया कि क्या हुआ है।

रामविचार नेताम,केदार कश्यप,दयालदास बघेल पुराने चेहरे पद पर आये जरूर पर शेष अधिकांश नए चेहरों को ही अधिक महत्व वर्तमान सत्ता में दिया गया है। महत्वपूर्ण विभागों का बटवारे में भी बाजी नए चेहरों के हाथ लगी है। नेतृत्व की बागडोर तीन से चार नए चेहरों के हाथ आ गयी है। इन लोगों के लिए जो एकमात्र अड़चन राजनैतिक रूप से समझी जा रही थी ,उसे दिल्ली की राह दिखा दी गई है।अब सत्ता की पूरी बागडोर नए नेतृत्व के हाथों में है। डॉ. रमनसिंह देश-प्रदेश के एक कद्दावर नेता ,उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। भले ही उनकी सीधी राजनीति में दखल ना दिखाई दे रही हो,पर उनके 15 साल के सरकार चलाने के दीर्घ प्रशासनिक अनुभव की अनदेखी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी उनकी उपयोगिता प्रदेश में बनी हुई है। कांग्रेस की तरफ देखें तो छत्तीसगढ़ की सत्ता गवानें के बाद भी भूपेश बघेल की पूछ परख हाई कमान में बनी हुई है। हाई कमान उन्हें उसी तरह महत्व दे रहा है ,जैसा देता आया है। सरकार जाने के बाद सब जानते और कहते भी हैं कि भूपेश बघेल को संगठन चलाने की जितनी महारत हासिल है उतनी सरकार चलाने में साबित नहीं हो पाई। दिल्ली संगठन में उन्हें बड़ा स्थान दिया जा सकता है। इस तरफ देखें तो राजनांदगांव में चुनाव हारने के बाद उनमें हताशा भले ही दिखाई ना दे रही हो। जिन लोगों ने धोका दिया उसकी कसक तो उनके दिल में जरूर होगी। इधर चुनाव के पहले चार छत्रप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में थे। भूपेश बघेल , टीएस सिंहदेव,.डॉ. चरणदास महंत , ताम्रध्वज साहू। अब चर्चा चरणदास महन्त की अधिक हो रही है ,कहा जा रहा है कि उनका राजनैतिक कद हाई कमान के दर पर पहले से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। कोरबा से उनकी धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत की जीत ने उन्हें यह सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी कि चारों छत्रपों का कद कहीं से हाई कमान के पास कम नहीं हुआ है। थोड़ा कुछ जरूर फर्क पड़ा है। यह भी कि महंत की पूछ परख कुछ ज्यादा ही दिखाई देगी, ऐसा राजनैतिक जानकारों का कहना है। संगठन के बारे में कहा जाए तो कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में आज का संगठन उतना मजबूत नहीं दिखता जितना मजबूत वो महंत व भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुआ करता था। कुछ यह भी कहा जा सकता है कि मोहन मरकाम के समय काम भले ही स्मूथ चल रहा दिखता था,पर संगठन जैसा उन्हें सौंपा गया वैसा ही चला पाए। कुछ आगे बढा हो ऐसा परिलक्षित नहीं हुआ। गुटबाजी अवश्य बढ़ गई थी। कुल मिला कर दोनों पार्टी में साफ दिखाई देने लगा है कि यह बदलाव का दौर है। पुराने चेहरे किनारे होंगें।उनका क्या उपयोग होगा यह समय पर ही पता चलेगा। नए चेहरे मुख्य धारा में प्रवेश करेंगें। पुराने चेहरों ने अपने दौर में अपना नाम चमकाया। अब बारी नए चेहरों की है। यह साफ दिखाई दे रहा है कि ताजी बयार बहने का समय आ गया है। तीसरी लाइन तक के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। दरी उठाने वाले कार्यकर्ता के चेहरे पर भी कुछ हल्की सी चमक देखी जा सकती है।

खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का बदला नाम: पूर्व मंत्री सिंहदेव ने कहा

योजना का नाम बदलना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं

रायपुर. छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रखा गया है. इसका आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया है. योजना का नाम बदलने को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है. नाम बदलने का फैसला खूबचंद बघेल का अनादर है.

पूर्व मंत्री सिंहदेव ने कहा, अगर सरकार नए सिरे से कुछ योजना चालू करते हैं तो उसे अपने हिसाब से नाम रखें. पहले से संचालित कार्यक्रम योजना का नाम बदलना सही नहीं है. ये बिलकुल स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. ऐसे में एक परिपाटी बन जाएगा. आज मैं हूं सत्ता में तो अपने हिसाब से नाम रखा, कल कोई और आया तो वह अपने हिसाब से नाम रखेगा. हम नाम रखने पर सवाल नहीं उठा रहे हैं.

नाम बदलने पर सवाल उठा रहे हैं. सरकार नई योजना, नया कार्यक्रम शुरू कर उसका नाम रख ले.

छत्तीसगढ़ में लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

अब सेमेस्टर सिस्टम से होगी पढ़ाई, सिलेबस में भी बदलाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जुलाई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू हो जाएगी. प्रेस कांफ्रेंस में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर प्रसन्ना ने बताया, अब वार्षिक पढ़ाई की जगह सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी. सिलेबस में भी बदलाव किया गया है. अतिथि व्याख्याता नीति भी लागू की गई है. नई नीति से उच्च शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है. उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना ने बताया, इस नीति में सतत मूल्यांकन का प्रावधान है, जिससे विद्यार्थियों के मानसिक उर्जा के साथ बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होगी. सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम होने के कारण विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव नहीं होगा.बहु-विषयक प्रणाली पर आधारित यह नीति विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार दूसरे संकाय के विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता देती है. पाठ्यचर्या में भारतीय ज्ञान पद्धति के समावेश के साथ पाठपेत्तर गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है. प्रोद्योगिकी के अनुकूलतम उपयोग पर बल दिया गया है.

जिन विद्यार्थियों को विषय विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने या शोध करने की इच्छा हो वे पाठ्यक्रम को निरंतर चौथे वर्ष में जारी रख सकते हैं एवं 'आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च' की उपाधि चौथे वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं. इस नीति के अंतर्गत बहु-विषयक शिक्षा, वैचारिक समझ एवं आलोचनात्मक सोच, नैतिक मूल्यों के साथ कौशल विकास को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है. सतत आतंरिक मूल्यांकन में 30% अंक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा में 70% अंकों का प्रावधान रखा गया है. विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए इन दोनों को मिलाकर (आतंरिक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा) कुल 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा. जेनेरिक एलेक्टिव के अंतर्गत कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय का विद्यार्थी अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय के किसी एक विषय को अपनी इच्छानुसार ले सकता है.

लिंचिंग और हत्या के आरोपियों का सरंक्षण और समर्थन असंवैधानिक

रायपुर। मॉब लिंचिंग के आरोपियों के समर्थन में राजधानी के सिटी कोतवाली के थाने के घेराव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना सभ्य समाज के लिए कलंक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हत्या और लिंचिंग के आरोपियों के समर्थन में भाजपा और आरएसएस के अनुसंगिक संगठनों के द्वारा सिटी कोतवाली थाने का घेराव, साय सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। भयमुक्त वातावरण प्रत्येक छत्तीसगढ़िया का अधिकार है, लेकिन साय सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होने लगी है।

बलौदाबाजार की घटना के लिए जिम्मेदार भाजपा के नेताओ को क्यो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा ?

रायपुर। एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा की बलौदाबाजार में षडयंत्रपूर्वक की गई गिरफ्तारी की निंदा करते हुये प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा की पहले से ही आशंका थी राज्य सरकार बलोदा बाजार की घटना से लगे दामन में काली दाग को लीपापोती करने के लिये कांग्रेस नेताओं पर झूठे मामला दर्ज करा गिरफ्तार करेगी। पहले सतनामी समाज के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया उनकी मांग को अनसुना किया गया उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा नेताओं को शामिल करवाया गया और अब घटना होने के बाद षडयंत्र पूर्वक कांग्रेस नेताओं को फसाया जा रहा है।

सड़क हादसे में 2 मेडिकल छात्रों की मौत, 5 गंभीर

रायपुर। राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह नेशनल हाईवे 53 पर मंदिरहसौद टोल नाका के पास दो कारों में जबरदस्त टक्कर होने से यह हादसा हुआ है। दोनों मृतक युवक रिम्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हुंडई क्रेटा क्र. जीजे 09 बीएफ 3996 में कुल 04 युवक सवार थे और रायपुर से मंदिरहसौद की तरफ जा रहे थे। वहीं दूसरी सुजुकी कंपनी की कार क्र सीजी 17 केयू 4250 में 03 युवक सवार थे और मंदिर हसौद से रायपुर की तरफ जा रहे थे।

श्री रामलला दर्शन के लिए 850 तीर्थयात्री दुर्ग से स्पेशल ट्रेन से हुए रवाना

रायपुर। अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के पश्चात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भांचा राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम ले जाने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरूआत की। आज इस योजना के अंतर्गत दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 850 यात्री दुर्ग स्टेशन से रवाना हुए। छत्तीसगढ़ के भांचा राम जय सियाराम जय सियाराम की सुमधुर ध्वनि से पूरा दुर्ग स्टेशन गुंजायमान हो गया। तीर्थयात्रियों ने श्री रामलला दर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन की बहुत अच्छी योजना है। हम सब इस दिव्य क्षण की बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज यह इंतजार पूरा हुआ। ननिहाल वासियों को अपने भांजे के दर्शन का अवसर सुलभ हुआ है। हम श्री रामलला से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व रायपुर एवं बिलासपुर संभाग के यात्री भी अयोध्याधाम के दर्शन कर चुके है। लोकसभा चुनाव में लगी आचार संहिता के उपरांत आज तीर्थयात्रा का पुन: शुभारंभ हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अयोध्याधाम जा रहे तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी है। आज दुर्ग रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 1 से इस स्पेशल ट्रेन को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरूण साव एवं विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप और विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा,ललित चंद्राकर, गजेन्द्र यादव व रिकेश सेन ने हरी झण्डी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.